

घटना घटना

सत्य के साथ... जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com अम्बिकापुर, वर्ष 22, अंक - 170- बुधवार 22 - अप्रैल 2026, पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रुपये RNI Reg. No.- CHHHH/2004/15050, डाक पंजीवन. कं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

केरलम में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट... 13 की मौत, 10 शव बरामद 3 लोगों के शरीर के हिस्से बिखरे मिले, 40 मजदूर काम कर रहे थे...

त्रिशूर, 21 अप्रैल 2026। केरलम के त्रिशूर जिले में मंगलवार दोपहर 3.30 बजे पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ। हदसे में 13 लोगों की मौत हो गई। फैक्ट्री में कई लोग झुलस गए। घायलों को आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक, मौके से 10 शव मिले, जबकि 3 लोगों के शरीर के हिस्से मिले हैं। 5 घायलों की हालत गंभीर है। 17 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। पटाखा खेतों के बीच बने शेड में बनाए जा रहे थे। हदसे के समय करीब 40 लोग मौजूद थे। फायर ब्रिगेड, पुलिस और रेस्क्यू टीमों मौके पर पहुंची, लेकिन रुक-रुक कर विस्फोट होने से रेस्क्यू में दिक्कत आई।



त्रिशूर पूरम पर्व के लिए तैयार किये जा रहे थे पटाखे
अधिकारियों ने बताया कि यह हादसा एक शेड में हुआ जहां मंदिर देवस्वामि की ओर से त्रिशूर पूरम पर्व के लिए पटाखें तैयार किए जा रहे थे। त्रिशूर पूरम पर्व 26 अप्रैल को है। घटना के बाद राज्य के सीएम पिनरई विजयन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि घायलों को हर संभव चिकित्सा सहायता प्रदान की जाए। उन्होंने बचाव और राहत कार्यों बुरती से करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने मुख्य सचिव से बात कर यह निर्देश दिया कि यदि आवश्यकता हो, तो गंभीर रूप से झुलसे लोगों के इलाज के लिए राज्य के बाहर के विशेषज्ञ चिकित्सकों की भी मदद ली जाए। मुख्यमंत्री ने लोगों की मौत पर गहरा शोक जताया है। राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे घायलों के लिए विशेष उचार तय करें। वीना जॉर्ज ने इमरजेंसी के लिए सरकारी एम्बुलेंस सेवा सहित अतिरिक्त एम्बुलेंस और चिकित्सा दलों को घटनास्थल पर तैनात करने को कहा है।

मृतकों के परिवार को 2-2 लाख का मुआवजा
पीएम मोदी ने हदसे में मरने वाले लोगों के लिए संवेदना जताई और मृतकों के परिवार को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50 हजार के मुआवजे का ऐलान किया है। पीएम ने कहा- जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूँ।

कांग्रेस ने पीएम मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन को लेकर विशेषाधिकार हनन का दिया नोटिस

नई दिल्ली, 21 अप्रैल 2026। संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष एवं कांग्रेस महासचिव (संगठन) केशी वेणुगोपाल (संगठन) के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 18 अप्रैल को राष्ट्र के नाम संबोधन को लेकर विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में विपक्षी सांसदों पर टिप्पणी की और उनके मतदान पैटर्न पर सवाल उठाए। वेणुगोपाल ने मंगलवार को लोकसभा अध्यक्ष को दिए पत्र में कहा कि प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों की आलोचना करते हुए उनके मतदान व्यवहार पर न केवल सवाल उठाए बल्कि उनके इरादों पर भी संदेह जताया। यह कार्य संसद के विशेषाधिकार का उल्लंघन और सदन की अवमानना है। प्रधानमंत्री का इस तरह का भाषण शक्ति का दुरुपयोग है और यह लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है। प्रधानमंत्री का यह संबोधन महिला आरक्षण से जुड़े



संविधान (131वां संशोधन) विधेयक-2026 के लोकसभा में पास नहीं होने के एक दिन बाद किया गया था। वेणुगोपाल ने कहा कि 16 एवं 17 अप्रैल को विपक्षी दलों के सभी सांसदों ने महिला आरक्षण का समर्थन किया था। उन्होंने 2023 में पारित 'नारी शक्ति वंदन' संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम का जिक्र करते हुए मांग की कि महिला आरक्षण को तत्काल लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि 131वें संशोधन विधेयक के जरिए सरकार ने अनुच्छेद 82 में बदलाव कर परि सीमन से जुड़ी संवैधानिक सुरक्षा को हटाने की कोशिश की।

विपक्ष का विरोध इसी कारण था, जबकि महिला आरक्षण के प्रति उनका समर्थन स्पष्ट और एकमत था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा विपक्षी सांसदों की नीयत पर सवाल उठाना उनके स्वतंत्रता और इमानदारी पर आक्षेप है। यह न केवल व्यक्तिगत हमला है बल्कि संसद की गरिमा और अधिकारों पर सीधा आघात है। यह विधेयक संविधान की मूल संरचना पर हमला था और उसका गिरना सही था। प्रधानमंत्री का इस पर नाराज होकर राष्ट्र को संबोधित करना और विपक्षी सांसदों पर आरोप लगाना लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है। वेणुगोपाल ने कहा कि संसद की परंपरा और अनुच्छेद 105 के तहत किसी भी सदस्य के भाषण या मतदान पर किसी व्यक्ति, यहां तक कि प्रधानमंत्री को भी टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। ऐसा करना संसद की गरिमा को कमजोर करता है और सांसदों के स्वतंत्र कर्तव्यों में हस्तक्षेप करता है।

बंगाल को भ्रष्टाचार, घुसपैठ और गुंडागर्दी से मुक्त कराने का चुनाव : अमित शाह

आसनसोल, 21 अप्रैल 2026। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कुल्टी विधानसभा सभा सीट के उम्मीदवार डा. अजय पट्टार के समर्थन में बलतोलिया गणेश पूजा मैदान में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने आसनसोल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य की ममता सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने जनता से सवाल करते हुए कहा कि क्या वे राज्य में बदलाव चाहते हैं, सिंडिकेट राज खत्म करना चाहते हैं और बंगाल को घुसपैठियों से मुक्त बनाना चाहते हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि आसनसोल की यह पवित्र भूमि कभी उद्योग और श्रम की पहचान रही है, जहां से पूरे देश और दुनिया में लोहा जाता था लेकिन वर्तमान सरकार ने यहां के उद्योगों को बंद करने का काम किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह चुनाव केवल किसी प्रत्याशी या कार्यकर्ता को जिताने का नहीं बल्कि पूरे बंगाल को भ्रष्टाचार, घुसपैठ और गुंडागर्दी से मुक्त कराने का चुनाव है। उन्होंने लोगों से अपील की कि



वे मतदान के दिन कमल के निशान पर बटन दबाकर भाजपा की सरकार बनाएं। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है और महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ी हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार बनने पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

गृहमंत्री ने वादा किया कि राज्य में अवैध खनन बंद किया जाएगा, रोजगार के नए अवसर पैदा किए जाएंगे और सरकारी योजनाओं को पारदर्शी तरीके से लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार बनने पर बेरोजगारों को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाएगी, गर्भवती महिलाओं को सहायता मिलेगी और महिलाओं के लिए बस यात्रा

सुगम की जाएगी। साथ ही, आयुष्मान भारत योजना को प्रभावी रूप से लागू कर गरीबों को पांच लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों को अधिक आर्थिक सहायता दी जाएगी और युवाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण सुविधा प्रदान की जाएगी। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता लाई जाएगी और बिना किसी भ्रष्टाचार के नियुक्तियां की जाएंगी। गृहमंत्री ने राज्य सरकार पर विभिन्न घोटालों के आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार बनने के बाद दोषियों को कानून के तहत सजा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा गरीबों की किसी भी योजना को बंद नहीं करेगी बल्कि नई योजनाएं शुरू करेगी। साथ ही, सीमाओं की सुरक्षा को मजबूत किया जाएगा ताकि घुसपैठ पूरी तरह रोक दी जा सके। उन्होंने कहा कि बंगाल का मुख्यमंत्री बंगाल का ही होगा और बाहरी व्यक्ति के मुख्यमंत्री बनने की अफवाहें मलत हैं।

सीमा राजभर बनी समाजवादी पार्टी महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिलेश यादव ने भाजपा पर बोला तीखा हमला

लखनऊ, 21 अप्रैल 2026। राजधानी लखनऊ में मंगलवार को समाजवादी पार्टी के मुख्यालय पर बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला, जहां कई नेताओं ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान बसपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता एमएच खान समेत श्यामलाल निषाद, विजय कुमार लाल, अखिलेश पाठक, इशरत अली खान और नीलू सत्याधी सपा में शामिल हुए। यह सभी नेता सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान सीमा राजभर को समाजवादी महिला सभा का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष भी घोषित किया गया। इस मौके पर अखिलेश यादव ने सरकार और भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने भाजपा की पदयात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि कड़ी धूप में बिना तैयारी के यात्रा करना दिखावटी राजनीति का हिस्सा है। उन्होंने दावा किया कि जनता अब बदलाव चाहती है और भाजपा की वापसी मुश्किल है। अखिलेश यादव ने एक चाय विक्रेता का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि उसकी दुकान बंद कराई गई, क्योंकि उसने बेहतर चाय बनाने का दावा किया था। उन्होंने कहा कि सरकार रोजगार देने में विफल रही है और छोटे कारोबारियों को भी परेशान किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने महिला आरक्षण मुद्दे पर भी सवाल उठाए और कहा कि सरकार की नीतियों में इमानदारी की कमी है। उन्होंने मुख्यमंत्री के बयान पर भी कटाख करते हुए भाजपा पर भ्रामक राजनीति करने का आरोप लगाया।



जनता दल यूनाइटेड की बैठक में विधायक दल के नेता चुने गए श्रवण कुमार



नई दिल्ली, 21 अप्रैल 2026। जनता दल यूनाइटेड ने अपने वरिष्ठ नेता श्रवण कुमार को विधायक दल का नेता चुन लिया है। यह निर्णय 21 अप्रैल 2026 को हुई पार्टी बैठक के बाद लिया गया, जिसकी पुष्टि बिहार विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी आधिकारिक पत्र में की गई। इससे एक दिन पहले नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई थी, लेकिन तब नेता के नाम पर अंतिम निर्णय नहीं हो पाया था। अब पार्टी नेतृत्व ने श्रवण कुमार के नाम पर सहमति जताते हुए औपचारिक घोषणा कर दी है। सूत्रों के मुताबिक, नई सरकार में उपमुख्यमंत्री पद न मिलने से श्रवण कुमार नाराज बताए जा रहे हैं। ऐसे में पहले उन्हें वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा दी गई और अब विधायक दल का नेता बनाकर उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश की गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह फैसला सामाजिक संतुलन को साधने की रणनीति का हिस्सा है। जदयू का पारंपरिक आधार 'लव-कुश' समीकरण पर टिका है, जिसमें कुर्मी और अन्य पिछड़े वर्गों की अहम भूमिका रही है। चूंकि श्रवण कुमार कुर्मी समुदाय से आते हैं, इसलिए उन्हें यह जिम्मेदारी देकर पार्टी ने जातीय संतुलन बनाए रखने का संदेश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने पूछा-छूने से देवता अपवित्र कैसे होते हैं सबरीमाला के वकील बोले... भगवान अय्यप्पा ब्रह्मचारी, इसलिए पूजा की प्रथा भी वैसी

नई दिल्ली, 21 अप्रैल 2026। सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री और धार्मिक भेदभाव से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। कोर्ट ने पूछा, 'मूर्ति छूना इश्वर का अपमान कैसे हो सकता है और वे अपवित्र कैसे हो जाते हैं।' सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, 'क्या संविधान उस भक्त की मदद के लिए आगे नहीं आया, जिसे केवल उसके वंश और जन्म के कारण देवता को छूने से रोक दिया जाता है।' इस पर सबरीमाला के वकील एडवोकेट वी. गिरी ने कहा कि सी भी मंदिर में होने वाले रीति-रिवाज उस धर्म का अभिन्न हिस्सा होते हैं। पूजा देवता की विशेषताओं के उलट नहीं हो सकती। भगवान अय्यप्पा 'नैतिक ब्रह्मचारी' हैं, इसलिए वहां की परंपराएं उसी के अनुरूप तय की गई हैं।



एडवोकेट सुब्रमण्यम ने कहा... विस्ती संप्रदाय विशेष के मंदिर पर सामाजिक सुधार का कानून लागू किया जा सकता है...

- एडवोकेट सुब्रमण्यम: किसी संप्रदाय विशेष के मंदिर पर सामाजिक सुधार का कानून लागू किया जा सकता है, जिसके तहत हिंदुओं के सभी वर्गों के लिए उसके दरवाजे खोल दिए जाएं।
- जस्टिस सुंदरेश: उदाहरण देकर बताए। एडवोकेट सुब्रमण्यम-पूजा के लिए बने सार्वजनिक संस्थान का अर्थ संप्रदाय विशेष के मंदिर भी हो सकते हैं। जस्टिस सुंदरेश: क्या कोई ऐसा संप्रदाय विशेष का मंदिर हो सकता है जो सार्वजनिक संस्थान न हो? हो सकता है कि वह हिंदू मंदिर हो, लेकिन सार्वजनिक संस्थान न हो।
- एडवोकेट सुब्रमण्यम: ऐसा भी हो सकता है जब वह किसी परिवार के सदस्यों के लिए समर्पित कोई निजी मंदिर हो।
- जस्टिस सुंदरेश: यह परिभाषित करके बताएं कि मंदिर के मामले में 'सार्वजनिक स्वराज्य' क्या है।

कांग्रेस अध्यक्ष खरगे की सफाई प्रधानमंत्री को आतंकवादी नहीं कहा



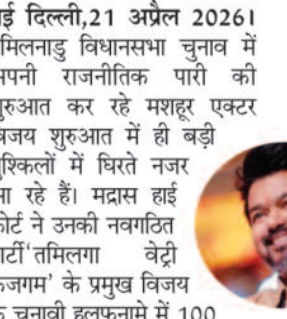
नई दिल्ली, 21 अप्रैल 2026। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मंगलवार को अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री को कभी आतंकवादी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि उनका आशय यह था कि प्रधानमंत्री लोकतांत्रिक ताने-बाने को डरा-धमका रहे हैं। खरगे ने चेन्नई में केशी वेणुगोपाल के साथ पत्रकार वार्ता में आईएडीएमके और भाजपा गठबंधन की आलोचना करते हुए प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहा दिया था। लेकिन जब पत्रकारों ने उनसे इस टिप्पणी के संदर्भ में सवाल किया तो उन्होंने कहा कि उनका मतलब था कि प्रधानमंत्री लोगों और राजनीतिक दलों को डराने-धमकाने का काम कर रहे हैं। इसके बाद खरगे ने कहा कि उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि प्रधानमंत्री आतंकवादी हैं। उनका आशय था कि प्रधानमंत्री अपनी शक्ति और सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल कर विपक्षी दलों पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने यह विवादित बयान एआईएडीएमके-भाजपा गठबंधन पर हमला करते हुए दिया था। उन्होंने कहा था कि ए आई ए डीएमके, जो अन्नादुरई की तस्वीर लगाती है, वह मोदी के साथ कैसे जा सकता है। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद खरगे ने अपने बयान को लेकर सफाई दी और कहा कि उनका आशय लोकतंत्र को कमजोर करने वाली राजनीति की ओर इशारा करना था।

अनिल अंबानी की कंपनी अहर्मान पर सीबीआई का बड़ा एक्टाव

19 हजार करोड़ के फर्जीवाड़े में 2 बड़े अधिकारी गिरफ्तार नई दिल्ली, 21 अप्रैल 2026। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने उद्योगपति अनिल अंबानी के मालिकाना हक वाली कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के खिलाफ बड़े कार्रवाई की है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर दर्ज किए गए धोखाधड़ी के एक मामले में सीबीआई ने कंपनी के दो वरिष्ठ अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए अधिकारियों की पहचान डी. विश्वनाथ और अनिल काल्या के रूप में हुई है। एम्बीआई का आरोप है कि कंपनी ने क्रेडिट सुविधाओं के नाम पर लिए गए फंड का गलत इस्तेमाल किया, जिससे अकेले एसबीआई को 2929.05 करोड़ रुपये का भारी नुकसान उठाना पड़ा है। एसबीआई द्वारा दी गई शिकायत के मुताबिक, इस बड़े फर्जीवाड़े के कारण कुल 17 बैंकों के करोड़ों रुपये की लगभग 19,694.33 करोड़ रुपये की भारी चपत लगी है। जांच एजेंसी की अब तक की तपतीश में यह सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि रिलायंस कम्युनिकेशंस के कई अधिकारियों ने मिलकर अलग-अलग शेल (फर्जी) कंपनियां बना रखी थीं।

चुनावी हलफनामों में 100 करोड़ का झोल... मद्रास हाई कोर्ट के रडार पर विजय, इनकम टैक्स को जांच के आदेश

नई दिल्ली, 21 अप्रैल 2026। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत कर रहे मशहूर एक्टर विजय शुरुआत में ही बड़ी मुश्किलों में घिरे नजर आ रहे हैं। मद्रास हाई कोर्ट ने उनकी नवगठित पार्टी 'तमिलनाडु वेद्री कजगम' के प्रमुख विजय के चुनावी हलफनामों में 100 करोड़ रुपये से अधिक की भारी गड़बड़ी पकड़ी है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने सीधे इनकम टैक्स विभाग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। पहली बार चुनावी मैदान में उतरी विजय की पार्टी के लिए इसे एक बहुत बड़ा राजनीतिक और कानूनी झटका माना जा रहा है।



दरअसल, एक्टर विजय ने तमिलनाडु चुनाव के लिए दो अलग-अलग विधानसभा सीटों, त्रिची और पेरम्बूर से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। विवाद तब शुरू हुआ जब पेरम्बूर के एक स्थानीय महादाता ने अदालत का दरवाजा खटखटाते हुए आरोप लगाया कि विजय द्वारा दोनों सीटों पर दिए गए हलफनामों में उनकी आय के आंकड़े मेल नहीं खा रहे हैं। जांच में सामने आया कि त्रिची सीट के लिए दाखिल कागजातों में विजय ने अपनी आय 220 करोड़ रुपये दिखाई थी, जबकि पेरम्बूर सीट के हलफनामों में यह आंकड़ा मात्र 115 करोड़ रुपये दर्शाया गया था।

पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु में चुनाव प्रचार थमा, 23 अप्रैल को मतदान

नई दिल्ली, 21 अप्रैल 2026। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में गुरुवार को होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार मंगलवार शाम 5 बजे थम गया। पश्चिम बंगाल के पहले चरण के लिए 152 सीटों और तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर 23 अप्रैल को मतदान होगा। चुनाव आयोग के अनुसार मंगलवार शाम 5 बजे से दोनो राज्यों में चुनाव प्रचार पूरी तरह थम गया और 'साइलेंस पीरियड' लागू हो गया। नियमों के मुताबिक मतदान से 48 घंटे पहले प्रचार अभियान पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया जाता है, ताकि मतदाता बिना किसी दबाव के स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकें। यह प्रावधान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के तहत लागू होता है। इस दौरान न तो रैलियां आयोजित की जा सकती हैं और न ही टीवी, अखबार या सोशल मीडिया पर प्रचार किया जा सकता है। नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। मतदान को बढ़ावा देने



और 100 प्रतिशत मतदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चुनाव आयोग ने राज्यभर में व्यापक जागरूकता अभियान शुरू किए हैं। तमिलनाडु में इस बार कुल 4,023 उम्मीदवार मैदान में हैं। यहां मुख्य मुकाबला द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (इएमके) और अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (अन्नाद्रमुक) के नेतृत्व वाले गठबंधन के बीच माना जा रहा है। वहीं अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी तमिलनाडु वेद्री कड़गम (टीवीके) के कारण कई सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय है। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के लिए 16 जिलों की 152 सीटों पर मतदान

होगा। इस चरण में कुल 1,478 प्रत्याशी मैदान में हैं और लगभग 3.60 करोड़ मतदाता अपने मतदाधिकार का प्रयोग करेंगे। मुर्शिदाबाद की 22, कुचबिहार की नौ, जलपाईगुड़ी की सात, अलीपुरद्वार की पांच, कलिंगों की एक, दार्जिलिंग की पांच, उत्तर दिनाजपुर की नौ, दक्षिण दिनाजपुर की छह, मालदा की 12, बोरभूम की 11, पश्चिम बर्द्धमान की नौ, पूर्व मेदिनीपुर की 16, पश्चिम मेदिनीपुर की 15, झाड़ग्राम की चार, पुरुलिया की नौ व बांकुरा की 12 सीटें शामिल हैं। पहले चरण में कुल 1,478 प्रत्याशी मैदान में हैं। मतदाताओं की कुल संख्या तीन करोड़ 60 लाख 77 हजार 171 है, जिनमें एक करोड़ 84 लाख 99 हजार 496 पुरुष, एक करोड़ 75 लाख 77 हजार 210 महिला व 465 ट्रांसजेंडर शामिल हैं। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से तुणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रही हैं, जहां उनकी सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी से है।

संपादकीय



आतंक के खिलाफ मजबूत मोर्चा

भारत दशकों से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष आतंकवाद का सामना करता आया है। यह लड़ाई हमारे लिए नई नहीं है। आतंकवाद कितना भी घोर हो सकता है, इसका एक उदाहरण पिछले वर्ष पहलगाम में हुआ आतंकी हमला था, जिसमें लोगों को उनका मजहब पूछकर मारा गया था। चूँकि पहलगाम हमले को बरसी निकट है, इसलिए हमें आतंकवाद के खतरों को लेकर सचेत रहना होगा। पहले जहाँ आतंकवाद सीमांत क्षेत्रों और पारंपरिक तरीकों तक सीमित था, वहीं अब यह उच्च तकनीक, इंटरनेट और अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क के सहारे तेजी से फैलने वाला वैश्विक खतरा बन गया है।

आज आतंकी केवल हथियारों के सहारे नहीं, बल्कि डिजिटल माध्यमों, गुप्त वित्तीय नेटवर्कों और वैचारिक प्रचार के जरिये भी काम कर रहे हैं। इस बदलते स्वरूप को समझ बिना आतंकवाद से प्रभावी ढंग से निपटना संभव नहीं है। इसी संदर्भ में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक समयानुकूल पहल की है। इसे नाम दिया है प्रहार (यानी प्रोएक्टिव रिस्पॉन्स ऑगंस्ट होस्टाइल एक्टर्स)। यह कदम आतंकवाद से निपटने में बाजी पलटने वाला वांव सिद्ध हो सकता है।

भारत ने आतंकवाद से लड़ते हुए कई अनुभव हासिल किए हैं। इस क्रम में माओवाद से निपटने में अपनाई गई समाधान संकल्पना एक उत्कृष्ट उदाहरण है। दूढ़ इच्छाशक्ति, स्पष्ट रणनीति, बेहतर समन्वय और मजबूत खुफिया तंत्र के माध्यम से उग्रवाद को काफी हद तक नियंत्रित किया गया। इससे यह सिद्ध हुआ कि यदि नीति स्पष्ट हो और एजेंसियों के बीच तालमेल मजबूत हो, तो जमीनी स्तर पर ठोस परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। हालांकि आतंक से निपटने में आज की चुनौतियां कहीं अधिक विकराल हैं। आतंकवाद मुख्यतः बाहरी ताकतों द्वारा पोषित है। अब बिखरे हुए छोटे-छोटे समूहों, अकेले काम करने वाले व्यक्ति और आनलाइन नेटवर्क के रूप में भी वह विस्तार ले रहा है। इस तरह यह एक साथ जमीनी, इंटरनेट और वित्तीय तंत्र तीनों स्तरों पर काम करता है। ऐसे में अलग-अलग और असंगठित प्रयास पर्याप्त नहीं होंगे।

प्रहार जैसी संकल्पना इन्हें पहलुओं को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। यह तकनीक, खुफिया जानकारी, कानून व्यवस्था, वित्तीय निगरानी और अंतरराष्ट्रीय सहयोग में समन्वयन को सुनिश्चित करती है। इसका उद्देश्य स्पष्ट है-खतरे को चिह्नित करना, उसे बढ़ने से रोकना और जरूरत पड़ने पर तुरंत और सख्त कार्रवाई करना। इस नीति की सबसे बड़ी विशेषता इसका समग्र दृष्टिकोण है। आतंकवाद बंदूक या बम का मामला नहीं है, बल्कि यह एक सोच, एक बड़े नेटवर्क और दुरमन के सुनियोजित षडयंत्र का हिस्सा है, इसलिए इसका समाधान भी बहुआयामी होना चाहिए। प्रहार सात मुख्य स्तंभों पर आधारित है, जो इसे एक संतुलित और प्रभावी नीति बनाते हैं।

एक स्तंभ है रोकथाम यानी खुफिया जानकारी के आधार पर समय रहते कार्रवाई। दूसरा स्तंभ है प्रतिक्रिया, जिसमें किसी घटना पर त्वरित एवं समन्वित कार्रवाई। तीसरा स्तंभ है विश्लेषण, जिसमें सटीक जानकारी एवं विश्लेषण के आधार पर निर्णय। चौथा स्तंभ है मानवाधिकार अनुपालन यानी कानून और संविधान के दायरे में रहकर कार्रवाई। पांचवां स्तंभ है आतंकी वित्तीय ढांचे की कमर तोड़ना, ताकि उन तक वित्तीय मदद पहुंचने ही न पाए। छठा स्तंभ है जागरूकता और कट्टरता-निरोध, जिसमें समाज को साथ लेकर चलना और दुष्प्रचार का समय से खंडना। सातवां स्तंभ है लचीलापन और पुनर्बाहली यानी घटना के बाद तेजी से सामान्य स्थिति बहाल करना। ये सभी स्तंभ ऐसी रणनीति बनाते हैं, जो न केवल आतंक को रोकने में सक्षम है, बल्कि समाज को भी मजबूत बनाती हैं।

आज आतंकी नई तकनीकों का तेजी से उपयोग कर रहे हैं। ऐसे में पारंपरिक पुलिसिंग पर्याप्त नहीं रह गई है। प्रहार इस कमी को दूर करते हुए साइबर क्षमता, आधुनिक तकनीक और वित्तीय निगरानी को भी अपने ढांचे में शामिल करता है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने आतंक के खिलाफ अपना रुख और स्पष्ट किया है। बालाकोट एयर स्ट्राइक से लेकर आपरेशन सिंदूर और देश के भीतर आतंकी नेटवर्क पर लगातार कार्रवाई यह दिखाती है कि भारत अब केवल बचाव की नीति तक सीमित नहीं है। जरूरत पड़ने पर उसके पास निर्णायक और पूर्व-निषेधात्मक कठोर कदम उठाने की क्षमता और इच्छाशक्ति दोनों मौजूद हैं। प्रहार यह सुनिश्चित करता है कि ऐसी कार्रवाई केवल परिस्थितियों पर निर्भर न रहे, बल्कि एक व्यवस्थित नीति के तहत की जाए। इस नीति का केंद्रीय आधार आतंकी रोकथाम है। इसके लिए खतरे को प्राथमिक स्तर पर ही चिह्नित कर उसे निष्प्रभावी करना मूल उद्देश्य है। इसके लिए खुफिया-आधारित पुलिसिंग को सुदृढ़ करना, एजेंसियों के बीच रियल-टाइम सूचना साझाकरण सुनिश्चित करना, भूतंत्र नेटवर्क को समय रहते ध्वस्त करना और आतंकी समर्थन तंत्र को समाप्त करना अनिवार्य है।

साथ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सक्रिय कट्टरपंथी गतिविधियों की निगरानी और आतंकी वित्तपोषण के स्रोतों पर कठोर नियंत्रण इस ढांचे के प्रमुख घटक हैं। एआई के माध्यम से संभावित खतरों का पूर्वानुमान, बिग डेटा से सदिग्ध पैटर्न की पहचान, सीमाओं पर ड्रोन निगरानी और साइबर फोरेंसिक के माध्यम से इन्फोस्टेज संचार की ट्रैकिंग जैसे उपाय इसे अधिक प्रभावी बनाते हैं। आतंकवाद के डिजिटल स्वरूप को देखते हुए साइबर क्षमताओं का विस्तार अब अनिवार्य हो गया है, क्योंकि डिजिटल आधारित दुष्प्रचार के बढ़ते उपयोग ने यह चुनौती और जटिल बना दी है। यह भी समझना होगा कि कट्टरपंथ केवल सुरक्षा बलों के माध्यम से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इसके लिए समाज, शिक्षकों, धार्मिक नेतृत्व और नागरिक संगठनों की भागीदारी भी अपरिहार्य है।

प्रहार भारत की आतंकवाद-रोधी रणनीति में बड़े बदलाव का प्रतीक है। इसका ढांचा मजबूत है और सरकार की मंशा भी स्पष्ट दिखती है, पर इसकी सफलता क्रियाच्यवन पर निर्भर करेगी। नीति बनाना पहला कदम है, उसे जमीन पर प्रभावी बनाना असली चुनौती है।

संतों की ई एम आई और मोक्ष का पैकेज

डॉ. सुरेश कुमार मिश्रा उरतूम
स्वामी डिजितलानंद का आश्रम किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी के मुख्यालय जैसा दिखता था। वहां मोक्ष की प्राप्ति के लिए कस्टमर केयर नंबर दिए गए थे। मदनलाल, जो अपने जीवन के पापों से डरा हुआ था, आश्रम पहुंचा। उसे एक रिस्पॉन्सिव मिली, जिसने वैराग्य का मेकअप कर रखा था। उसने पूछा, सर, आप कौन सा निर्वाण पैकेज लेना चाहेंगे? हमारे पास सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम श्रेणी है। मदनलाल ने पूछा, इनमें फर्क क्या है? रिस्पॉन्सिव ने समझाया, सिल्वर में आपको 100 साल स्वर्ग मिलेगा, पर वहां आपको कॉमन डोरमेटरी में रहना होगा। गोल्ड में प्राइवेट क्लाइड मिलेगा और प्लैटिनम में आप सीधे ईश्वर के साथ सेल्फी ले सकेंगे और इसे सीधे पृथ्वी पर कास्ट कर सकेंगे।

सूचना

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटीक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।
—सम्पादक

महिला आरक्षण बिल : किसे होगा नफा किसे नुकसान



मुस्ताअली बोहरा भापाल, मध्यप्रदेश

लोकसभा में महिला आरक्षण बिल दो दिनों की बहस के बाद लोकसभा में 131वां संशोधन विधेयक खारिज हो गया। केंद्र ने संसद का विशेष सत्र बुलाया था जो 16 अप्रैल को शुरू हुआ और 18 अप्रैल तक चला। 12 साल के शासन में मोदी सरकार को संसद में पहला बड़ा झटका लगा। महिला आरक्षण बिल खारिज हो जाने के बाद राजनीति भी तेज हो गई है। बीजेपी इस बिल के पास ना हो पाने का ठीकरा विपक्ष पर फो रहीं है तो विपक्ष ने इसे राजनीतिक एजेंडा करार दिया है। तुणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी ने सदन में तीनों विधेयकों का विरोध करते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री को जब लगता है कि वो चुनाव हार जाएंगे तो वो नियम ही बदल देते हैं, ये विधेयक सिर्फ राजनीतिक मकसद से लाए जा रहे हैं। कांग्रेस

सांसद कार्ति चंद्रबर्म ने कहा कि ये समझने की जरूरत है कि महिला आरक्षण विधेयक साल 2023 में ही पारित हो चुका है। सदन में परिसीमन के जरिए दक्षिण भारतीय राज्यों का हक मारने की साजिश की हर हुई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि हम महिला आरक्षण को परिसीमन से जो ने से कभी सहमत नहीं हो सकते। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जयराम रमेश, समाज वादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ ही एमके स्टालिन ने भी इसे साजिश करार दिया था। दूसरी तरफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा था कि महिलाओं को आरक्षण देना समय की मांग है और जो इसका विरोध करेगा वह लंबे समय तक इसकी कीमत चुकाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के नुक संदेश भी दिया। इस पूरे घटनाक्रम से एक बात तो साफ हो गई कि महिला बिल को बीजेपी काफी सोच समझकर संसद में लाई थी। मोदी सरकार ने लोकसभा में तीन विधेयक पेश किए थे। पहला, संविधान (131वां संशोधन) विधेयक 2026, दूसरा, परिसीमन विधेयक 2026 और तीसरा विधेयक केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक 2026। संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 का उद्देश्य नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 जिसे महिला आरक्षण अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, उसमें संशोधन करना था। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को संसद ने सितंबर



2023 में लगभग सर्वसम्मति से पारित किया था। इसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान था। यह विधेयक लोकसभा में आगे नहीं बढ़ा पाया। सदन के नियमों के अनुसार, संविधान संशोधन विधेयक उचित संदर्यों के दो तिहाई बहुमत से ही पारित हो सकता था। पक्ष में 298 सांसदों के वोट पड़े जबकि 230 सांसदों ने विरोध में वोट डाला। इसके बावजूद विधेयक को जरूरी दो तिहाई बहुमत नहीं मिल पाया। लोकसभा में 537 सांसद हैं और विधेयक को पास करने का जादूई आंके 1360 वोट था। सत्ताह्व एनडीए में 240 भाजपा सांसदों सहित 293 सदस्य हैं, जिसमें पर 67 सीटों की कमी रह गई। भाजपा ने महिला बिल पास ना होने को लेकर अभी से सियासी माहौल बनाना शुरू कर दिया है। तो दूसरी तरफ, कांग्रेस भी हमलावर है। तर्क दिया जा रहा

है कि किसी राजनीतिक पार्टी की पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस से थी एनी बेसेंट, देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कांग्रेस से थी श्रीमती इंदिरा गांधी, पहली महिला मुख्यमंत्री कांग्रेस से थी सुचेता कृपलानी, देश की पहली महिला राष्ट्रपति कांग्रेसनीत शासनकाल में थी श्रीमती प्रतिभा पाटिल, पहली महिला न्यायाधीश भी कांग्रेस के शासन में थी फातेमा बीबी। कांग्रेस का सवाल है कि बीजेपी चुनाव में महिलाओं को अधिक टिकट क्यों नहीं देती, मंत्री मंडल में अधिक महिलाओं को शामिल नहीं किया जाता, सरकारी नौकरियों में महिलाओं का आरक्षण कोटा क्यों नहीं बढ़ाया जाता। राहुल गांधी भी कह चुके हैं कि महिला आरक्षण बिल तो 2023 में पारित हो चुका है, जो बिल लाया गया वो एएससी-एस्टडी और ओबीसी के खिलाफ है। बहरहाल मोदी सरकार के एक दशक से ज्यादा कार्यकाल में एक भी बिल नहीं गिरा।

जितने भी बिल पेश किए गए, सभी संसद में पास हुए लेकिन पहली बार इतना अहम बिल लोकसभा में गिर गया। मालूम हो कि पिछले 24 साल के दौरान कोई भी सरकारी बिल नहीं गिरा था। साल 2002 में पोटा बिल गिरा था। उसके 24 साल बाद कोई बड़ा बिल सदन में गिरा है। 12 साल में मोदी सरकार का पहला बड़ा बिल गिरा है। ऐसा तो हो नहीं सकता, बीजेपी के थिंक टैंक को इसका अंदाजा नहीं था, या वो इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके पास विधेयक पास करने लायक बहुमत नहीं है। तो क्या भाजपा ये बिल यूपी और बंगाल चुनाव के नजरिए से लाई थी। इसके अलावा अगले लोकसभा चुनाव में महिला मतदाताओं को विपक्ष से दूर कर अपने पक्ष में लुभाने के लिए बीजेपी ने यह बिल नहीं किया था। वैसे भी, महिला मतदाताओं का साथ बीजेपी को मिलता रहता है। बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री माड्री लाइकी बहीण योजना और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाइली बहना योजना आदि का जादू चुनाव में दिख ही चुका है। ये तो तय है कि महिला आरक्षण बिल पास ना होने को भाजपा सियासी हथियार बनाएगी। हालांकि, पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों से तय हो जाएगा कि ये मुद्दा किसे नफा और किसे नुकसान पहुंचाता है। साथ ही अगले साल यूपी और फिर अन्य राज्यों के विधानसभा और 2029 में लोकसभा चुनाव तक ये मुद्दा बना रहता है या भी नहीं।

पृथ्वी को स्वच्छ सुंदर सुवासित बनाना ही होगा



प्रमोद दीक्षित मलय बांदा, उत्तरप्रदेश

मानव जीवन में अगर कोई सम्बंध सर्वाधिक उदात्त, गरिमावान, पावन और प्रेमपूर्ण है तो वह है मां और पुत्र का सम्बंध। एक मां कभी भी अपनी संतान को भूखा-प्यासा, निर्बल और कष्ट का जीवन जीते नहीं देख सकती और ऐसा कोई पुत्र भी नहीं होगा जो मां की कराह सुन न सके और व्यथित न हो। यही कारण है कि ऋषियों ने पृथ्वी की वन्दना माता के रूप में की। 'माता भूमिः पुत्रोऽपृथिव्याः' अथर्ववेद का यह सूत्र वाक्य धरती और मानव के सम्बंधों की न केवल गरिमावान व्याख्या करता है बल्कि धरती के प्रति मानवीय कर्तव्यों का निर्धारण भी। न केवल मानव के जीवन यापन के लिए बल्कि पशु-पक्षियों के लिए भी। 'यूज एण्ड शे' जीवन शैली के भवरजाल में फंसा प्लास्टिक कचरा के रूप में हजारों टन कूड़ा प्रतिदिन घरों से बाहर फेंक रहा है। इस प्लास्टिक में से अधिकांश रिसायकिल नहीं हो पाता। यह गलत नहीं है और अपने अवयवों में टूटने में 1000 साल लगाता है। एक आंकड़ा के मुताबिक भारत में प्रतिवर्ष 50 मीट्रिक टन प्लास्टिक का निर्माण होता है। विश्व में 10 करोड़ टन प्लास्टिक का उत्पादन अकेले अमेरिका प्रतिवर्ष करता है और एक करोड़ टन को तायपमान बढ़ रहा है। अन्तरराष्ट्रीय संस्था आई पी सी सी के एक अध्ययन के अनुसार, पिछली सदी में धरती का औसत तापमान 1.4 फ़ारनेहाइट बढ़ा है। यह वृद्धि मौसम और जलवायु के विनाशकारी परिवर्तन का कारण बनी है। तीव्र औक्साइड, रिफ्लिजेंट और शीत भंडारण केन्द्रों से उत्सर्जित क्लोरो फ्लोरो कार्बन से सूर्य की हानिकाक परावैगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करने वाली ओजोन परत में बड़े-बड़े छेद हो गये हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइ ऑक्साइड की मात्रा एक अनुमान के अनुसार 37.16



गीगा टन हो गई है। प्रति एके पैदावार बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अधाधुंध प्रयोग से मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरा शक्ति तो नष्ट हुई ही है बल्कि माटी भी जहरीली हो गई है। इस जहर के कारण मिट्टी को खाकर उसे खाद में बदलने वाले किसानों के मित्र केचुआ और अन्य छोटे कीट अब नहीं दिखते। दूध, अन्न, सब्जियां और भूभाग जल प्रदूषित हुआ है। परिणाम त्वचा रोग, टायफाइड, मस्तिष्क ज्वर, फाइलेरिया, दमा, कैसर जैसे रोग जड़ें जमा रहे हैं और महामारी जैसा रूप ले रहे हैं। कल-कारखानों से निकलने वाला दूषित जल बिना किसी ट्रीटमेंट के सीधे नदियों में डाला जा रहा है। यमुना आज दिल्ली-आगरा में गंदे नाले का रूप ले चुकी है। गंगा का जल अपना औषधीय गुण खो चुका है। गंगजल पीने और नहाने लायक नहीं बचा। गोमती अस्तित्व बचाये रखने को जूझ रही है। यही हाल कमोबेश अन्य नदियों का भी है। वरुणा और अरुनी नदियों के चतुर्दिक बसी होने के कारण काशी नगरी वाराणसी कहलाई लेकिन आज दोनों नदियां शहर का मल-मूत्र और कचरा ढोने को विवश हैं। नदियां कारखानों का अपशिष्ट बहाने के माध्यम बन कर रह गई हैं।

तथाकथित विकास के नाम पर बड़े बांध बनाकर नदियों के प्राकृतिक प्रवाह को बांधा गया। बड़े बांधों के बनने से जैव विविधता खत्म हुई है। पहाड़ के सीने में उा आए कंक्रीट के जंगल ने प्राकृतिक परिवेश पर आघात किया है। धरती को बचाये रखने के लिए ही सितम्बर 1969 में सिएटल में अमेरिकी सीनेटर जेराल्ड नेल्सन ने 1970 के बसन्त में पर्यावरण को लेकर राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन की घोषणा

की ताकि लोग पर्यावरण की हो रही क्षति को समझ सकें। 1990 में पहली बार अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर इसे मनाने का निश्चय किया जिसमें 141 देशों के 20 करोड़ लोगों की सहभागिता रही। हालांकि, 21 मार्च 1970 को संघ के तत्कालीन महासचिव यू थॉट ने 'पृथ्वी दिवस' को अन्तरराष्ट्रीय समारोह स्वीकार किया था। 1992 में रियो डी जिनेरियो में संयुक्त राष्ट्र पृथ्वी सम्मेलन हुआ। ग्लोबल वार्मिंग के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए स्वच्छ ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा देने का संकल्प लिया गया। 2009 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाने का का निर्णय लिया। प्रत्येक वर्ष वैश्विक आयोजन की एक थीम तय की जाती है। वर्ष की थीम है-हमारी शक्ति, हमारा ग्रह। चीन, पाकिस्तान, भारत और अमेरिका सहित कई देशों ने पृथ्वी दिवस के सन्दर्भ में पर्यावरण के महत्व को स्वीकारते हुए विभिन्न मूल्य वर्ग के डक टिकट जारी किए हैं। यदि हम धरती को बचाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी के हाथों में एक हरी-भरी सुंदर, स्वच्छ, सदानारी और सुवासित वसुभरा सौंपें तो हमें अपनी दैनिक जीवनचर्या पूर्णरूपेण बदलनी होगी। हमें प्रकृति की ओर लौटना होगा। बाजार से सामान लाने के लिए घर से जूट या कपड़े के बने थैले उपयोग में लाएं। अनाज भण्डारण के लिए प्लास्टिक बोरियों की बजाय जूट के बोरे इस्तेमाल करें। रोजमर्रा के काम जैसे किराना, शाक-भाजी की खरीददारी में कागज के लिफाफों का प्रयोग करें जो किसी को रोजगार देगा और हमें संतुष्टि। किसानों को रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों की बजाय जैविका खाद और इको फेंडली देशी कीटनाशकों के इस्तेमाल के लिए प्रेरित-प्रोत्साहित करें। पहले खुरद से शुरू करनी होगी। विश्वास करिए, एक चलना आरम्भ करेगा तो साथ में लोग जुड़ते चले जायेंगे। केवल एक दिन पृथ्वी दिवस मनाये जाने भर से परिवर्तन होना वाला नहीं है। हमें हर दिन पृथ्वी दिवस मनाना होगा और प्रकृति के साथ चलना होगा, जीना होगा। तभी यह धरा बचेगी और हम भी।

धरा को बचाने के लिए जनभागीदारी जरूरी है...



लाल बिहारी ताल, नई दिल्ली

देश दुनिया में पर्यावरण का तेजी से क्षति होते देख अमेरिकी सीनेटर जेराल्ड नेल्सन ने 7 सितंबर 1969 को घोषणा की कि 1970 के बसंत में पर्यावरण

हिस्सा लिया। इसके आगे हर साल यह प्रक्रिया चलती रही। सन 2007 में पृथ्वी दिवस का अब तक के सबसे बड़ा आयोजन हुआ जिसमें अनुमानतः हजारों स्थान पर जैसे-कीव, यूकेन, कानवास, बेनजुएला, तुवालू, मनिला, फिलीपींस, टोगो, मैड्रिड, स्पेन, लन्दन, और न्यूयार्क के करोड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। विकास के इस अंधी दौड़ में पेड़ों की अंधाधुन कटाई, जालारण में कार्बन मोनो अक्साइड, कार्बन डाई अक्साइड, सल्फर, सीसा, पारा आदि के साथ-साथ कल-कारखानों के द्वारा धुआ एवं कचरा, कृषि में कीटनाशकों का अधिकाधिक प्रयोग आदी से धरती की बाढ़ एवं आन्तरिक दशा काफी दयनीय हो रही है।



पर राष्ट्रव्यापी जन साधारण प्रदर्शन किया जायेगा। उनकी मुहिम रंग लायी और इसमें 20 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया। और उनके समर्थन में जानेमाने फिल्म और टी.वी. के अभिनेता एड्री अल्बर्ट ने पृथ्वी दिवस के निर्माण में एक अहम भूमिका अदा किया। यही कारण है कि उनके जन्म दिन 22 अप्रैल के अवसर पर 1970 के बाद हर साल पृथ्वी दिवस मनाया जाने लगा। एल्बर्ट को टी.वी.शो ग्रीन एक्सर्स में भूमिका के लिए भी जाना जाता है। 141 देशों के पहल पर 1990 में 22 अप्रैल को पूरी दुनिया में विश्व स्तर पर पृथ्वी दिवस के मुद्दे को उठाया गया जिसमें पुनः चक्रोकरण के प्रयास को उत्साहित किया गया। और 1992 में रियो डी जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे करवाया। इस सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग एवं स्वच्छ ऊर्जा को प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया। सन 2000 में इंटरनेट ने पूरी दुनिया के कार्यकर्ताओं को एक मंच पर जोड़ने में मदद की जिससे यह मुद्दा ग्लोबल हो गया। वर्ष 2000 में 22 अप्रैल को 500 समूह 192 देशों के करोड़ों लोगों ने

पृथ्वी की इस दशा को सुधारने के लिए दुनिया के तमाम देश चिंतित हैं। उनमें भारत भी एक है। गांधी जी ने भी पर्यावरण पर चिंता व्यक्त करते हुए पृथ्वी मां की रक्षा के लिए सकारात्मक कदम उठाने की एकाग्रता की थी। इसके लिए काफी प्रयास भी हुए। प्रौद्योगिकी मंत्रालय से पर्यावरण एवं कृषि मंत्रालय से वन विभाग काटकर तात्कालिन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नेतृत्व में 1986 में एक अंगल मंत्रालय पर्यावरण एवं वन कर्मचारी का गठन किया गया। इसके बाद जल संरक्षण, भूमि संरक्षण और एवं वायु संरक्षण, वन संरक्षण आदि के लिए काफी नियम बनाये गए फिर भी पृथ्वी से अत्यधिक खनन जारी है। इसके रोकने के लिए सरकार को सख्त कदम उठाना होगा तभी इस मी रुपी पृथ्वी को बचाया जा सकता है। वरना पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी के नष्ट होने से समस्त जीव-जन्तु नष्ट हो जायेंगे। इसके लिए जरूरी है कि जीवों के इस संकट को समझना ही होगा और पृथ्वी के प्रति अपना दायित्व निभाना होगा तभी पृथ्वी बच पायेगी और जीवों का कल्याण हो पायेगा।

त्योहारों पर 'कल्चरल अटैक'

रहा है? 'कल्चरल अटैक' शब्द भले ही आक्रमक प्रतीत होता हो, लेकिन इसका आशय किसी एक वर्ग या समूह पर आरोप लगाना नहीं है। यह उस धीमी, सूक्ष्म और कई बार अनदेखी प्रक्रिया की ओर संकेत करता है, जिसके माध्यम से परंपराएं अपने मूल सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ से हटकर नए अर्थ ग्रहण करने लगती हैं। यह परिवर्तन कभी स्वाभाविक होता है, तो कभी सुनियोजित आर्थिक और वैचारिक प्रभावों का परिणाम भी हो सकता है। भारतीय त्योहारों की जड़ें मुख्यतः कृषि और प्रकृति से जुड़ी रही हैं। देश का

अधिकांश समाज सदियों तक कृषि-आधारित रहा है, इसलिए फसल, मौसम और भूमि के साथ उसका गहरा रिश्ता था। फसल कटने की खुशी, नई बुवाई की शुरुआत, वर्षा के आगमन का स्वागत-ये सब त्योहारों के माध्यम से व्यक्त होते थे। इन उत्सवों में किसान केंद्र में होता था, क्योंकि यही अन्न का उत्पादक था और यही समाज की जीवन-रेखा को बनाए रखता था। ऐसे त्योहारों में आडंबर कम और सहभागिता अधिक होती थी। लोग मिलकर गाते-बजाते, सामूहिक भोज करते और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते

थे। लेकिन जैसे-जैसे समाज में शहरीकरण बढ़ा, औद्योगिकीकरण हुआ और भूमि की ताकतें मजबूत हुईं, त्योहारों का स्वरूप भी बदलने लगा। अब त्योहारों को केवल सांस्कृतिक या सामाजिक दृष्टि से नहीं, बल्कि आर्थिक अवसर के रूप में भी देखा जाने लगा। बाजार ने त्योहारों को उपभोग से जोड़ दिया-जहाँ खरीदारी, सजावट और प्रदर्शन को प्रमत्तता मिलने लगी। त्योहारों के साथ 'ऑफर', 'डिस्काउंट' और 'शुभ खरीदारी' जैसे विचार जुड़ गए, जिसने उनके मूल स्वरूप को प्रभावित किया। अब बदलाव केवल बाहरी नहीं है, बल्कि मानसिकता में भी आया है। पहले त्योहारों का अर्थ था-मिलना-जुलना, साझा करना और प्रकृति

के प्रति आभार व्यक्त करना। अब कई जगहों पर यह प्रतिस्पर्धा का रूप ले चुका है-किसने कितना खर्च किया, किसने क्या खरीदा, किसका आयोजन कितना भव्य था। इस प्रक्रिया में त्योहारों की आत्मा कहीं पीछे छूटती चली गई। त्योहारों पर 'कल्चरल अटैक' की चर्चा करते समय एक और महत्वपूर्ण पहलु सामने आता है-लोक परंपराओं का हाथिए पर जाना। भारत में हर क्षेत्र की अपनी विशिष्ट परंपराएं रही हैं, जो स्थानीय जीवनशैली, भाषा और संस्थाओं से जुड़ी होती थीं। लेकिन आज मीडिया और बाजार के प्रभाव में एक प्रकार की सांस्कृतिक एकसूपता देखने को मिल रही है।

बाइक चोरी का खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार

जिला अस्पताल व मिशन अस्पताल से चुराई थीं गाड़ियां, 7 बाइक बरामद

-संवाददाता- अम्बिकापुर, 21 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)।

शहर में लगातार हो रही दोपहिया वाहन चोरी के मामलों में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना लुंड्रा और मणपुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 7 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पुलिस के अनुसार, भगवानपुर सुभाषनगर निवासी शिवम रवानी की बाइक 9 अप्रैल को जिला अस्पताल परिसर से चोरी हो गई थी। मामले में मणपुर थाना में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की गई। विवेचना के दौरान पुलिस ने संदिग्ध दीपक प्रजापति (23) निवासी बरगोडीह, थाना लुंड्रा को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में आरोपी ने शहर और आसपास के क्षेत्रों से बाइक चोरी करना स्वीकार किया। उसने बताया कि फरवरी माह में ग्राम चांदो (लखनपुर) में अपने साथियों के साथ मिलकर पहली बाइक चोरी की थी, जिसके बाद लगातार अलग-अलग स्थानों को निशाना बनाया। आरोपी ने मिशन अस्पताल, जिला अस्पताल और महामाया चौक सहित



अन्य जगहों से कुल 7 बाइक चोरी की। इनमें से 6 बाइक उसने अपने घर में छुपाकर रखी थी, जबकि एक बाइक अपने साथी जावेद खान (28) निवासी बरगोडीह को दे दी थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को कब्जे से सभी बाइक जब्त कर ली हैं। दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश

किया गया, जहाँ से उन्हें जेल भेज दिया गया है। कार्रवाई में थाना प्रभारी लुंड्रा निरीक्षक प्रदीप जायसवाल, थाना प्रभारी मणपुर उप निरीक्षक सीपी तिवारी, साइबर सेल प्रभारी सहायक उप निरीक्षक अजीत मिश्रा, सहायक उप निरीक्षक अनिल सिंह, प्रधान आरक्षक भोजराज पासवान, नरेन्द्र जांगड़े, देवनायण

चौधरी, विकास सिन्हा, रजनीकांत मिश्रा, सतीश सिंह, सूरज राय, अजय पाण्डेय, आरक्षक उमाशंकर साहू, रामशंकर यादव, निरंजन बड़ा, मनीष सिंह, अशोक यादव, विकास मिश्रा, अनिल सिंह, रामकेशव, अरविन्द, इबनुल खान एवं अन्य स्टाफ सक्रिय रहे।

अम्बिकापुर में गांजा तस्करी का खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार

3.4 किलो गांजा, स्कूटी और नकदी जब्त, सप्लायर भी पुलिस गिरफ्त में...

-संवाददाता- अम्बिकापुर, 21 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)।

कोतवाली पुलिस ने अवैध गांजा तस्करी के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 3 किलो 400 ग्राम गांजा, एक स्कूटी, नकदी और मोबाइल जब्त किया है। जब्त मशरूका की कुल कीमत करीब 1 लाख 25 हजार रुपए आंकी गई है। पुलिस के अनुसार 20 अप्रैल को मुखबिर से सूचना मिली कि घुटारापारा नहर रोड पर एक युवक सफेद रंग की स्कूटी में गांजा लेकर बिक्री के लिए ग्राहक का इंतजार कर रहा है। सूचना पर टीम ने मौके पर घेराबंदी कर संदिग्ध युवक को पकड़ा। पूछताछ में उसने अपना नाम शाहबाज आलम (24) निवासी मोमिनपुर अम्बिकापुर बताया। तलाशी लेने पर स्कूटी की डिकी से 3.4 किलो गांजा बरामद हुआ, जिसकी कीमत लगभग 70 हजार रुपए है। साथ ही घटना में प्रयुक्त स्कूटी (कीमत करीब 50 हजार रुपए) भी जब्त की गई। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने यह गांजा मोमिनपुरा निवासी मो. इजाज से 8 हजार रुपए में



खरीदा था और बाकी रकम बिक्री के बाद देने की बात तय हुई थी। इसके आधार पर पुलिस ने सप्लायर मो. इजाज (47) को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जहाँ उसने लेनदेन से गांजा लाकर बेचने की बात कबूल की। पुलिस ने सप्लायर के पास से 8 हजार रुपए नकद और एक मोबाइल भी जब्त किया है। दोनों आरोपियों को खिलाफ एन-डीपीएस एक्ट की धारा 20 (बी) के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया है। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक शशिकांत सिन्हा सहित पुलिस टीम के अन्य अधिकारी और जवान सक्रिय रूप से शामिल रहे।

ट्रक की टक्कर से बाइक सवार की मौत

सीतापुर के सरईपारा में सुबह हुआ हादसा, चालक ट्रक छोड़कर फरार

-संवाददाता- अम्बिकापुर, 21 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)।



नेशनल हाइवे 43 पर मंगलवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। ग्राम सरईपारा स्थित रासम मिल के पास तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार जशपुर जिले के ग्राम लुंड्रा निवासी मुनेश्वर प्रधान (44) सुबह काम के सिलसिले में सीतापुर आया था। काम खत्म कर वह अपनी बाइक (सीजी 13 ए 6414) से वापस घर लौट रहा था। इसी दौरान सुबह करीब 8 बजे सामने से आ रहे मालवाहक ट्रक (सीजी 29 एबी 0147) से उसकी सीधी टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार सड़क पर गिर पड़ा और सिर में गंभीर चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन मौके पर जुट गए, जिससे कुछ देर के लिए हाइवे पर आवागमन बाधित रहा। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, भीड़ को नियंत्रित किया और यातायात बहाल कराया। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर थाने ले लिया है। वहीं मृतक के चचेरे भाई की रिपोर्ट पर अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।

ग्रीष्मकालीन प्रतियोगिताओं से निखरेगा विद्यार्थियों का कौशल, 27 अप्रैल से होगा विकासखंड स्तरीय आयोजन

-संवाददाता- एमसीबी, 21 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)।

जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर अंतर्गत संचालित शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के ज्ञान, रचनात्मकता एवं कौशल विकास को प्रोत्साहित करने हेतु ग्रीष्मकालीन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। Language - Numeracy Skill Based Summer Competition 2026 के माध्यम से विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। यह प्रतियोगिता जिले के सभी संकुलों के विद्यार्थियों की भागीदारी के साथ प्रत्येक विकासखंड में 27 अप्रैल 2026 को आयोजित की जाएगी। इसके पश्चात विकासखंड स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी 04 मई 2026 को आयोजित जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। प्रतियोगिता में प्राथमिक स्तर (कक्षा 3 से 5) एवं माध्यमिक स्तर (कक्षा 6 से 8) के विद्यार्थी सम्मिलित होंगे। इसमें चित्र देखकर कहानी लेखन, प्रश्नोत्तरी, डिक्शनरी खोजो, शब्दों से वाक्य निर्माण, सुवक्त्र, मापन तथा 'कबाड़ से जुगाड़' जैसी कुल 7 विधाओं में एकल एवं समूह दोनों श्रेणियों में प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी।

मीषण गर्मी में पशुओं को हीट स्ट्रोक से बचाने एडवाइजरी जारी

पशुपालन विभाग की अपील-छाया, ठंडा पानी और संतुलित आहार का रखें खास ध्यान

-संवाददाता- अम्बिकापुर, 21 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)।



सरगुजा जिले में बढ़ती गर्मी और लू के असर को देखते हुए पशुपालन विभाग ने पशुपालकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। विभाग ने पशुओं को हीट स्ट्रोक (लू) से बचाने के लिए विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। अतिरिक्त उपसंचालक डॉ. सीके मिश्रा ने बताया कि अधिक तापमान के कारण पशुओं की सेहत पर बुरा असर पड़ता है और दुग्ध उत्पादन भी घट सकता है। ऐसे में

उंडी और हवादार जगह पर रखें। शेड के ऊपर टाट, घास या सफेद पेंट का उपयोग कर तापमान कम किया जा सकता है। दोपहर में पशुओं को धूप में न बांधें। शेड के आसपास छायादार पेड़ होना भी फायदेमंद है। पशुओं को दिन में 3-4 बार ताजा और ठंडा पानी पिलाएं। पानी में नमक, गुड़ या इलेक्ट्रोलाइट मिलाना लाभकारी है। दिन में 1-2 बार पशुओं को नहलाएं। चारा सुबह-शाम दें और आहार में हरा चारा शामिल करें।

लक्षणों को न करें नजरअंदाज : तेज सांस लेना, हांफना, मुंह खोलकर सांस लेना, लार टपकना या सूखी दिखना लू के संकेत हो सकते हैं। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत सतर्क हो जाएं।

तुरंत करें इलाज

लक्षण दिखने पर पशु को छाया में ले जाकर सिर और गर्दन पर ठंडा पानी डालें। साथ ही नजदीकी पशु चिकित्सक से तुरंत संपर्क करें। पशुपालन विभाग ने किसानों से अपील की है कि भीषण गर्मी में पशुओं की विशेष देखभाल करें, ताकि उनकी उत्पादन क्षमता बनी रहे।

नेशनल हाइवे से स्टॉपर चोरी करने वाला ट्रैलर चालक गिरफ्तार

-संवाददाता- बलरामपुर, 21 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)।



राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगाए गए शासकीय स्टॉपर चोरी करने वाले ट्रैलर चालक को बलरामपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहाँ से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार, 20 अप्रैल को थाना क्षेत्र के बड़कीमहरी तिराहा के पास ट्रैलर वाहन क्रमांक सीजी 07 बीए 2389 के चालक ने वाहन में हुए मामूली नुकसान की भरपाई के लिए हाइवे पर गति नियंत्रण हेतु यातायात पुलिस द्वारा लगाए गए शासकीय स्टॉपर चोरी कर ट्रैलर में लौट कर लिया था। मुखबिर से सूचना मिलने पर यातायात पुलिस ने डुमरखी ढाबा के पास ट्रैलर को रोककर जांच की। इस दौरान वाहन से चोरी किए गए 2 नग स्टॉपर बरामद किए गए।

मामले में आरोपी चालक गिरीश नारायण यादव (28), निवासी ग्राम जमुई, थाना सेलमपुर, जिला देवरिया (उत्तरप्रदेश) के खिलाफ अपराध क्रमांक 65/2026 धारा 305 (ई) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से करीब 30 हजार रुपए कीमत के 2 स्टॉपर और घटना में प्रयुक्त ट्रैलर वाहन जब्त किया है। पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आरोपी को 21 अप्रैल को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से उसे न्यायिक रिमांड पर जिला जेल भेज दिया गया।

टीएस सिंह के सुझाव पर बनेगा लखनपुर बायपास व लेमरू में वन्यजीव-अनुकूल सड़क

-संवाददाता- अम्बिकापुर, 21 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)।



पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव द्वारा केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को प्रेषित सुझाव पत्र के उपांगत अब अम्बिकापुर-कटघोरा मार्ग पर प्रस्तावित फोरलेन रोड पर लखनपुर में बाईपास के साथ ही साथ लेमरू प्रोजेक्ट के क्षेत्र में वन्य-जीवन अनुकूल सड़क का निर्माण होगा। उल्लेखनीय है कि अम्बिकापुर से कटघोरा के मध्य राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 130 को अपग्रेड कर इसे फोरलेन में बदलने की स्वीकृति हो गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग सलाहकार कंपनी के माध्यम से इसके डीपीआर पर काम कर रही है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग का एक बड़ा हिस्सा सरगुजा, सूरजपुर एवं कोबा जिले में उस वन्यक्षेत्र से गुजरता है जिसे लेमरू हाथी प्रोजेक्ट के रूप में अधिसूचित किया गया है। अतिरिक्त इस मार्ग पर सरगुजा जिले में लखनपुर बस्ती भी है जहाँ बायपास के अभाव में यातायात का भारी दबाव नगर के बीच से गुजरने वाले

लिए यहाँ बायपास बनाने का था। वहीं दूसरा सुझाव लेमरू हाथी रिजर्व क्षेत्र में इस सड़क के विस्तार को लेकर था। पूर्व उपमुख्यमंत्री ने यह सुझाव दिया था कि इस क्षेत्र में बन रहे इस फोरलेन सड़क को भारत माला प्रोजेक्ट के उन नॉर्म के तहत बनाया जाये जिससे इस क्षेत्र के वन्यजीवों को संरक्षण मिले। उन्होंने सुझाव देते हुए पत्र में उल्लेख किया था कि लेमरू हाथी प्रोजेक्ट क्षेत्र में एनिमल बेरिंकेटिंग के साथ ही पर्याप्त संख्या में एनिमल अंडरपास बनाये जाएं। पूर्व उपमुख्यमंत्री के सुझावों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग ने 20 अप्रैल को इस मार्ग के लिए डीपीआर बना रही सलाहकार संस्था को इस अनुरूप आवश्यक संसोधन कर डीपीआर देने हेतु पत्र जारी किया, साथ ही पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव को इस बाब में अवगत कराया है। पूर्व उपमुख्यमंत्री ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री का आभार जताया है कि उन्होंने इस क्षेत्र के निवासियों और उनके पर्यावरणीय हितों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया है।

नलजल योजना के पानी विवाद ने लिया हिंसक रूप, युवक का सिर फोड़ा



-संवाददाता- कुसुमी, 21 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)।

बलरामपुर जिले के ग्राम इंदरीकला में नलजल योजना के पानी को लेकर विवाद हिंसक हो गया। दबंगों ने एक युवक के साथ मारपीट कर पत्थर से उसका सिर फोड़ दिया और जान से मारने की धमकी दी। घटना के

बाद पीड़ित ग्रामीणों के साथ कलेक्टर और एसपी कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। जानकारी के अनुसार, ग्राम इंदरीकला नवापारा निवासी मोहम्मद तौफीक ने बताया कि गांव में नलजल योजना के तहत बनी पानी टंकी से पेयजल सप्लाई को लेकर ग्रामीणों ने सरपंच से शिकायत की थी। आपस में हिंसक और यथार्थ

अंसारी पानी का उपयोग अपनी खेती के लिए अधिक मात्रा में कर रहे हैं, जिससे ग्रामीणों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। बताया गया कि 20 अप्रैल को इसी मुद्दे पर बातचीत के दौरान विवाद बढ़ गया। आरोपियों ने मोहम्मद तौफीक के साथ मारपीट की और पत्थर मारकर उसका सिर फोड़ दिया। साथ ही ज्यादा नेता बनने की बात कहकर जान से

मारने की धमकी दी। पीड़ित ने घटना की शिकायत कुसुमी थाना में लिखित आवेदन देकर की है। साथ ही सुरक्षा की मांग को लेकर बलरामपुर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को भी आवेदन सौंपा गया है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के हितों से जुड़े मुद्दों को उठाने के कारण पुरानी रंजिश में यह हमला किया गया है।

850 तीर्थयात्रियों को लेकर अयोध्या धाम के लिए रवाना हुई विशेष ट्रेन महापौर श्रीमती मंजूषा भगत ने हरी झंडी दिखाकर गंतव्य के लिए किया रवाना

-संवाददाता- अम्बिकापुर, 21 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)।

इस जल्ये में शामिल हैं। ब्लॉकवार यात्रियों का विवरण देते हुए बताया कि जनपद अम्बिकापुर : 17 यात्री उदयपुर : 18 यात्री, लखनपुर : 14 यात्री, लुण्ड्रा : 13 यात्री, बलीही: 11 यात्री, सीतापुर : 11 यात्री, मैनापट: 12 यात्री, नगर निगम अम्बिकापुर: 30 यात्री नगर पंचायत लखनपुर: 05 यात्री और नगर पंचायत सीतापुर: 07 यात्री शामिल हुए हैं।

रांसद ने यात्रियों से की मुलाकात

ट्रेन के प्रस्थान से पूर्व सरगुजा सांसद श्री चिंतामणि महाराज ने स्टेशन परिसर में तीर्थयात्रियों से आत्मीय मुलाकात की। उन्होंने यात्रियों का कुशलक्षेम जाना और उनकी सुखद व मंगलमय यात्रा के लिए अपनी शुभकामनाएं प्रेषित कीं। सरगुजा संभाग के अंतर्गत जिलों के लिए शासन द्वारा कुल 850 यात्रियों का कोटा निर्धारित किया गया है, जिसमें सरगुजा के लिए 170, जशपुर के लिए 204, बलरामपुर-रामानुजगंज के लिए 164, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के लिए 57, कोरिया के लिए 108 तथा सूरजपुर के लिए 147 यात्रियों की संख्या तय की गई है। जिला स्तरीय नोडल अधिकारी एवं उप संचालक समाज कल्याण विभाग, श्री वी.के. उके ने बताया कि सरगुजा जिले से कुल 138 तीर्थयात्री



समापति श्री हरमिंदर सिंह टिन्नी, क्षेत्रीय अधिकारी (टूरिज्म बोर्ड) श्री आशीष वर्मा, जिले के जनप्रतिनिधिगण, पार्षदगण सहित रेलवे, आई.आर.सी.टी.सी. और समाज कल्याण विभाग के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।

अम्बिकापुर में निजी स्कूल के खिलाफ शिकायत, युवा कांग्रेस नेता ने एफआईआर की मांग की



-संवाददाता- अम्बिकापुर, 21 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)।

प्रदेश युवा कांग्रेस के महासचिव विष्णु सिंह देव ने शहर के एक निजी विद्यालय के खिलाफ थाना कोतवाली में शिकायत आवेदन देकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। शिकायत में विद्यालय पर कथित भेदभाव, अवैध संचालन और आर्थिक अनियमितताओं के गंभीर आरोप

लगाए गए हैं। विष्णु सिंह देव ने आरोप लगाया है कि विद्यालय ने एक बच्चे को स्थानीय भाषा बोलने के आधार पर प्रवेश देने से इंकार किया, जो शिक्षा के अधिकार और समानता के सिद्धांतों के विपरीत है। साथ ही विद्यालय के बिना वैध मान्यता लंबे समय से संचालित होने का भी आरोप लगाया गया है। शिकायत में विद्यालय द्वारा फीस, किताब, ड्रेस और अन्य मदों में अभिभावकों से बड़ी राशि वसूले जाने की जांच

की मांग की गई है। इसके अलावा जिला शिक्षा अधिकारी की भूमिका की भी निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई करने की मांग उठाई गई है। शिकायतकर्ता ने कहा है कि यदि प्रशासन उचित कार्रवाई नहीं करता है तो मामले को न्यायालय तक ले जाना जाएगा। फिलहाल प्रशासन और विद्यालय प्रबंधन की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। जांच के बाद ही आरोपों की पुष्टि हो सकेगी।

01 मई से 10 जून तक ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में लगेंगे शिविर सुशासन शिविर में लोगों की समस्याओं का किया जाएगा समाधान : जिला पंचायत सीईओ अभिषेक कुमार



-संवाददाता-
जशपुरनगर, 21 अप्रैल 2026
(घटती-घटना)।
जिला पंचायत सीईओ श्री अभिषेक कुमार ने सोमवार को कलेक्टर सभाकक्ष में साप्ताहिक समय सीमा की बैठक लेकर सुशासन शिविर के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आमजन की समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी निराकरण के उद्देश्य से इस वर्ष भी 'सुशासन तिहार 2026' के आयोजन व्यापक पैमाने पर किया जाएगा। इस संबंध में सभी जनपद पंचायत सीईओ को शिविर के लिए ग्राम पंचायतों में जगह का चिह्नकन करने और अभियान के सफल आयोजन को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों को पारदर्शी, सरल एवं त्वरित सेवाएं उपलब्ध कराना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। गत वर्ष आयोजित सुशासन तिहार के सकारात्मक परिणामों को देखते हुए इस वर्ष इसे और

अधिक व्यापक रूप में संचालित किया जाएगा। जिला पंचायत सीईओ ने बताया कि 30 अप्रैल तक लंबित प्रकरणों का निराकरण किया जाना है। इसके साथ ही विगत वर्ष के सुशासन शिविर के लंबित प्रकरणों का भी निराकरण गंभीरता से करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में बताया गया कि आगामी 30 अप्रैल 2026 तक जिले में लंबित प्रकरणों के निराकरण हेतु विशेष अभियान चलाया जाए। इसके अंतर्गत भूमि संबंधी प्रकरण जैसे नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, मनरेगा अंतर्गत लंबित मजदूरी भुगतान, हितग्राही मूलक योजनाओं के लंबित भुगतान, आय-जाति-निवासी प्रमाण पत्र, बिजली एवं ट्रांसफार्मर संबंधी समस्याएं तथा हैडपंप सुधार जैसे मुद्दों का प्राथमिकता से समाधान सुनिश्चित किया जाए। साथ ही पात्र हितग्राहियों को उज्वला योजना, राशन कार्ड, आयुष्मान भारत एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसी योजनाओं का लाभ दिलाने पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं। इस अवसर पर



सहायक कलेक्टर श्री अनिकेत अशोक, उपर कलेक्टर श्री प्रदीप कुमार साहू सभी एसडीएम और जिला स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित थे।
01 मई से 10 जून तक लगेंगे जन समस्या निवारण शिविर : सुशासन तिहार के अंतर्गत 01 मई से 10 जून 2026 तक प्रदेशभर में जन समस्या निवारण शिविरों का आयोजन किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में 15 से 20 ग्राम पंचायतों के समूह तथा शहरी क्षेत्रों में वार्ड क्लस्टर के आधार पर शिविर आयोजित

मुख्यमंत्री करेंगे विकास कार्यों का औचक निरीक्षण एवं समीक्षा बैठकें
अभियान के दौरान मुख्यमंत्री श्री साय स्वयं विभिन्न जिलों में पहुंचकर विकास कार्यों और योजनाओं के क्रियान्वयन का औचक निरीक्षण करेंगे तथा हितग्राहियों से फीडबैक लेंगे। इसके साथ ही जिला मुख्यालयों पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित कर समाधान शिविरों में प्राप्त आवेदनों के निराकरण की स्थिति एवं योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री द्वारा निरीक्षण एवं समीक्षा बैठक के उपरांत प्रेस वार्ता को संबोधित किया जाएगा तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों एवं नागरिकों से भेंट कर सुझाव प्राप्त किए जाएंगे। जिला पंचायत सीईओ ने साप्ताहिक समय सीमा की बैठक में आश्रम छात्रावास के नोडल अधिकारी को हार्स्टल का निरीक्षण करने के लिए 112 बिन्दुओं की जानकारी देने के लिए निर्देश दिये।
इन्होंने बताया कि जिला पंचायत सीईओ ने बताया कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि अभियान के दौरान मंत्री गण, सांसद एवं विधायक गण, मुख्य सचिव एवं प्रभारी सचिव समय-समय पर शिविरों में शामिल होकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण करेंगे और आमजन से संवाद स्थापित करेंगे।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आगडीह एयरस्ट्रिप पहुंचे,हुआ आत्मीय स्वागत



-संवाददाता-
जशपुरनगर, 21 अप्रैल 2026
(घटती-घटना)।
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आगडीह एयरस्ट्रिप पहुंचे। जहां जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने उनका आत्मीय स्वागत किया।

स्वागत करने वालों में सांसद श्री राधेश्याम राठिया, विधायक श्रीमती रायमुनी भगत, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री सालिक साय, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री शौर्य प्रताप सिंह जुदेव, नगर पालिका उपाध्यक्ष श्री यश प्रताप सिंह जुदेव, आईजी

श्री दीपक कुमार झा, कलेक्टर श्री रोहित व्यास, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ लाल उमदे सिंह, वनमण्डलाधिकारी श्री शशि कुमार, जिला पंचायत सीईओ श्री अभिषेक कुमार सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि गण और अधिकारी शामिल थे।

मंडी बोर्ड उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 26 अप्रैल को, 19 केंद्रों पर 4,855 अभ्यर्थी होंगे शामिल

-संवाददाता-
कोरिया/सूरजपुर, 21 अप्रैल 2026
(घटती-घटना)।
छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड के अंतर्गत उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2026 का आयोजन आगामी 26 अप्रैल (रविवार) को किया जाएगा, परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं, जिले में कुल 19 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 4,855 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। वहीं यह परीक्षा प्रदेश के 16 जिलों में एक साथ आयोजित की जा रही है।
सुबह 10 से 12:15 बजे तक होगी परीक्षा

काला या नीला बॉल पेन ही साथ लाने की अनुमति दी गई है, अनुचित साधनों का उपयोग करते पाए जाने पर अर्हता निरस्त करने की चेतावनी भी प्रशासन ने दी है।
सुरक्षा और निगरानी के पुख्ता इंतजाम
परीक्षा के सुचारु संचालन के लिए प्रशासन ने व्यापक तैयारियों की हैं, सभी केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में वीक्षक तैनात किए जाएंगे, अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रशिक्षण 24 एवं 25 अप्रैल तक पूरा कर लिया जाएगा, इसके अलावा परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी और महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी, ताकि परीक्षा पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न हो सके।
प्रशासन की अपील
जिला प्रशासन ने सभी अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें और समय का विशेष ध्यान रखें, समय पर केंद्र पहुंचकर सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने से किसी भी प्रकार की परेशानी से बचा जा सकता है, यह परीक्षा हजारों अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अवसर है, ऐसे में अनुशासन और नियमों का पालन ही सफलता की पहली शर्त होगी।

घंटे पहले अपने परीक्षा केंद्र पहुंचें, इससे फ्रिंकिंग और फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र के सत्यापन की प्रक्रिया समय पर पूरी हो सकेगी, साथ ही, अभ्यर्थियों को परीक्षा से एक दिन पहले अपने केंद्र का अवलोकन करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि परीक्षा दिवस पर किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। कड़े नियमों का करना होगा पालन-परीक्षा में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इस कोड के तहत अभ्यर्थियों को हल्के रंग के आधी बांह वाले कपड़े पहनकर आना अनिवार्य होगा, जबकि गहरे रंग के कपड़े प्रतिबंधित रहेंगे, फुटवियर के रूप में केवल चपल की अनुमति होगी, इसके अलावा किसी भी प्रकार के आभूषण, विशेषकर कान के आभूषण, पहनने की मनाही रहेगी।
प्रतिबंधित वस्तुओं पर पूरी रोक
परीक्षा केंद्र में मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, घड़ी, पर्स, बेल्ट, टोपी, स्कार्फ आदि ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है, केवल

जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक संपन्न... सांसद श्री राठिया ने केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन करने के लिए निर्देश

-संवाददाता-
जशपुरनगर, 21 अप्रैल 2026
(घटती-घटना)।
जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक आज लोक सभा क्षेत्र रायगढ़ के सांसद श्री राधेश्याम राठिया की अध्यक्षता में जिला पंचायत के सभाकक्ष में आयोजित की गई। सांसद श्री राठिया ने सभी अधिकारियों को केन्द्र और राज्य शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जल संरक्षण संवर्धन के कार्यों को बेहतर तरीके से संचालित करने के लिए कहा ताकि भू-जल स्तर अच्छा हो सके और किसानों को खेती बाड़ी करने में आसानी हो। जशपुर में सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए भी बेहतर कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा जशपुर के विकास कार्यों के लिए हर संभव सहयता करने की बात कही। इस अवसर पर जशपुर विधायक श्रीमती रायमुनी भगत, नगर पालिका अध्यक्ष श्री अरविन्द भगत, नगर पालिका उपाध्यक्ष श्री यश प्रताप सिंह जुदेव, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री शौर्य प्रताप सिंह जुदेव, कलेक्टर श्री रोहित व्यास वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ



लाल उमदे सिंह डीएफओ श्री शशि कुमार जिला पंचायत सीईओ श्री अभिषेक कुमार और सभी जिला स्तरीय अधिकारीगण बैठक में उपस्थित थे। कलेक्टर श्री रोहित व्यास ने बताया कि बगीचा विकास खंड के नहरों का जीर्णोद्धार करने के लिए मनरेगा और जल संसाधन विभाग की टीम गठित की जाएगी और छुटे हुए नालों का चिह्नकन किया जाएगा और शीघ्र ही प्रस्ताव शासन को भेज दिया जाएगा ताकि किसानों को खेती के लिए पर्याप्त पानी की सुविधा मिल सके। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत स्वीकृत सड़कों के कार्यों को गंभीरता से लेते हुए समय सीमा में पूर्ण कर लिया जाएगा। राष्ट्रीय सामाजिक सहयता कार्यक्रम



के तहत पात्र हितग्राहियों को पेंशन दिया जा रहा है। जल जीवन मिशन गांटी योजना के तहत 85 प्रतिशत लक्ष्य पूर्ण कर लिया गया है। एनआरएलएम योजना के तहत 1 लाख 45 हजार 775 दिए गए लक्ष्य में 1 लाख 39 हजार 651 पूर्ण कर लिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक 1 लाख 18 हजार 820 दिए गए लक्ष्य में से 90 हजार 630 आवास पूर्ण कर लिया गया है। प्रधानमंत्री जन मन आधुनिकीकरण कार्यक्रम, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सर्व शिक्षा अभियान, महिला बाल विकास विभाग, मिड डे मील योजना, प्रधानमंत्री उज्वला योजना, खनिज न्याय निधि, एकीकृत विद्युत विकास योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, आदि विभिन्न योजनाओं की विस्तार से समीक्षा किए।

टीबी मुक्त भारत अभियान (100 दिवसीय) के दूसरे चरण का शुभारंभ, हाई रिस्क क्षेत्रों में विशेष स्क्रीनिंग अभियान जारी



-संवाददाता-
एमसीबी, 21 अप्रैल 2026
(घटती-घटना)।
जिले में टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत 100 दिवसीय विशेष अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ 24 मार्च 2026 को किया गया। कलेक्टर डी. राहुल वेंकट के निर्देशानुसार एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अविनाश खरे के मार्गदर्शन में जिले में टीबी उन्मूलन हेतु व्यापक स्तर पर स्वास्थ्य गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। अभियान के अंतर्गत 25 मार्च 2026 से जिले के हाई रिस्क ग्रामों में आयुष्मान आरोग्य शिविर आयोजित कर हैड-हेल्ड एक्स-रे मशीन के माध्यम से सघन स्क्रीनिंग की जा रही है। अब तक जिले के 18 हाई रिस्क ग्रामों में शिविर लगाकर कुल 1386 व्यक्तियों का एक्स-रे परीक्षण किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त उप जेल मनेन्द्रगढ़ में भी विशेष स्वास्थ्य शिविर आयोजित कर 128 बंदियों को हैड-हेल्ड एक्स-रे मशीन से स्क्रीनिंग की गई। सदिग्ध मामलों की पुष्टि के लिए 546 संभावित टीबी मरीजों की NAAAT जांच कराई गई, जिसमें 17 नए टीबी मरीजों की पहचान कर उनका उपचार प्रारंभ कर दिया गया है।
राशन सर्वे एवं चिह्नकन पर विशेष जोर
अभियान के तहत आगामी दिनों में सभी हाई रिस्क ग्रामों में आयुष्मान आरोग्य शिविरों का आयोजन जारी रहेगा। साथ ही स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं एवं मितानिनों द्वारा घर-घर जाकर स्क्रीनिंग की जा रही है। उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों का प्रपत्र तैयार कर 'निश्चय आईडी' के माध्यम से उन्हें चिह्नित किया जा रहा है तथा आवश्यकतानुसार एक्स-रे एवं जांच सुनिश्चित की जा रही है।
जनमहोत्सवों में मिलेगा अभियान का बल
जिला प्रशासन ने आमजन, जनप्रतिनिधियों, संस्थाओं एवं कॉरपोरेट संगठनों से अपील की है कि वे 'निश्चय मित्र' बनकर टीबी मरीजों को गोद लें और उन्हें पोषण आहार उपलब्ध कराएं। इससे मरीजों के उपचार में तेजी आएगी और अभियान को सफलता मिलेगी। प्रशासन द्वारा विश्वास व्यक्त किया गया है कि जनसहभागिता एवं सतत प्रयासों के माध्यम से जिले को टीबी मुक्त बनाने के लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर हुआ जा सकेगा।

चिलचिलाती धूप में जनसेवा की मिसाल... सांसद चिंतामणि महाराज का भावुक कर देने वाला सूरजपुर प्रवास

सुख-दुख में साथ सूरजपुर में सांसद चिंतामणि महाराज का संवेदनशील दौरा
प्रोटोकॉल से परे जनसेवा गांव-गांव पहुंचे सांसद चिंतामणि महाराज
बिना बुलाए पहुंचे सांसद, ग्रामीण बोले—ऐसा जनप्रतिनिधि पहली बार देखा
शादी हो या शोक, हर जगह पहुंचे सांसद चिंतामणि महाराज

—संवाददाता—
सूरजपुर, 21 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)।
तपती धूप, व्यस्त कार्यक्रम और लगातार दौरे के बीच यदि कोई जनप्रतिनिधि बिना औपचारिकता के आम लोगों के सुख-दुःख में शामिल हो जाए, तो वह केवल राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि संवेदनशील जनसेवा का उदाहरण बन जाता है, ऐसा ही दृश्य हाल ही में सूरजपुर जिले में देखने को मिला, जहां सांसद चिंतामणि महाराज का दौरा जनमानस के दिलों को छू गया।

संगठनात्मक कार्यक्रमों से शुरू हुआ दौरा
जारी कार्यक्रम के तहत सांसद ने अपने प्रवास की शुरुआत भाजपा जिला कार्यालय में उपस्थित दर्ज कर संगठनात्मक गतिविधियों में भाग लेकर की। यहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर संगठन को मजबूत करने पर चर्चा की, इसके बाद वे विभिन्न सामाजिक आयोजनों में शामिल हुए और स्थानीय स्तर पर अपनी सक्रियता दिखाई।

विवाह समारोहों में दी शुभकामनाएं
अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सांसद ने भाजपा जिला महामंत्री शशिकांत गंग के परिवार में आयोजित वैवाहिक समारोह में भाग लेकर नवदंपति को आशीर्वाद दिया। इसके साथ ही भैयाथान में भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारी अमन प्रताप सिंह के विवाह समारोह में भी उन्होंने अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई, इसके अतिरिक्त उन्होंने ग्राम पंचायत रैसरी में रामकुमार पैकरा की पुत्री ज्योति, ग्राम पंचायत चेन्द्रा में रामरतन की पुत्री ललिता, ग्राम भाड़ी में शिवनंदन राम

शोक की घड़ी में भी पहुंचे संवेदना व्यक्त करने

इस दौरे का सबसे भावुक पहलू तब सामने आया, जब व्यस्त कार्यक्रमों के बीच सांसद को सूरजपुर नगर के प्रतिष्ठित व्यापारी प्रहलाद राय अग्रवाल के परिवार में शोक की सूचना मिली, सूचना मिलते ही उन्होंने अपने कार्यक्रम में बदलाव किया और तुरंत शोकाकुल परिवार के बीच पहुंच गए, उन्होंने के.के. अग्रवाल की धर्मपत्नी के निधन पर परिजनों से मुलाकात कर गहरी संवेदनाएं व्यक्त कीं, उनके इस आत्मीय व्यवहार ने शोक संतप्त परिवार को संबल दिया और वहां मौजूद लोगों की आंखें नम हो गईं।

बिना निर्मंत्रण गांव-गांव पहुंचना बना चर्चा का विषय

इस पूरे दौरे की सबसे खास बात यह रही कि सांसद कई स्थानों पर बिना किसी औपचारिक निर्मंत्रण के पहुंचे। ग्रामीणों ने भावुक होकर कहा कि उनके जैसे साधारण परिवारों के घर सांसद का आना किसी सपने से कम नहीं है, ग्रामीणों का कहना था कि आज तक ऐसा बहुत कम देखने को मिला है कि कोई जनप्रतिनिधि बिना बुलाए उनके सुख-दुःख में शामिल हो, सांसद का यह व्यवहार लोगों के बीच गहरी छाप छोड़ गया है।

की पुत्री दिया कुमारी और रामहरन पैकरा की पुत्री के विवाह समारोह में भी शामिल होकर नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया।



चिलचिलाती धूप में लगातार जनसंपर्क

—तेज गर्मी और कठिन परिस्थितियों के बावजूद सांसद का लगातार गांव-गांव जाकर लोगों से मिलना, उनका हालचाल जानना और हर वर्ग के बीच सहजता से घुलना-मिलना यह दर्शाता है कि उनका जुड़ाव केवल औपचारिक नहीं, बल्कि वास्तविक है, यह दौरा इस बात का प्रमाण बनकर सामने आया कि जनप्रतिनिधि यदि चाहे तो सीमित संसाधनों और कठिन परिस्थितियों में भी जनता के बीच सक्रिय रह सकता है।

जनता के बीच बढ़ी सराहना

सांसद चिंतामणि महाराज के इस दौरे की चर्चा अब पूरे क्षेत्र में हो रही है, लोग खुले तौर पर उनकी सराहना कर रहे हैं और इसे जनसेवा की सच्ची मिसाल बता रहे हैं, स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसे जनप्रतिनिधि ही लोकतंत्र की वास्तविक ताकत होते हैं, जो केवल मंचों तक सीमित न रहकर सीधे जनता के बीच पहुंचते हैं और उनके सुख-दुःख में सहभागी बनते हैं।



संवेदनशील नेतृत्व की झलक

सूरजपुर में सांसद का यह प्रवास केवल एक औपचारिक दौरा नहीं रहा, बल्कि यह संवेदनशील नेतृत्व का उदाहरण बन गया है, चाहे विवाह का अवसर हो या शोक की घड़ी—हर परिस्थिति में उपस्थित रहकर उन्होंने यह संदेश दिया कि सच्चा जनप्रतिनिधि वही है, जो हर समय जनता के साथ खड़ा रहे, उनका यह दौरा आने वाले समय में जनप्रतिनिधियों के लिए एक मानक के रूप में देखा जा सकता है, जहां जनसेवा केवल शब्दों तक सीमित न होकर व्यवहार में भी दिखाई देती है।

छात्र हित में बड़ा फैसला : आउट ऑफ सिलेबस प्रश्नों पर हजारों छात्रों को मिले 7 बोनस अंक

—संवाददाता—
सूरजपुर, 21 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)।

जिले में कक्षा चौथी की वार्षिक परीक्षा 2026 के हिंदी प्रश्नपत्र में सामने आई गंभीर त्रुटि के बाद शिक्षा विभाग ने छात्र हित में बड़ा और राहतभरा निर्णय लिया है, प्रश्नपत्र में आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए 7 अंकों के प्रश्नों को लेकर उठे विवाद के बाद अब जिले के सभी विद्यार्थियों को 7 बोनस अंक प्रदान करने के आदेश जारी किए गए हैं, इस निर्णय से हजारों छात्रों को सीधा लाभ मिला है और परीक्षा परिणाम पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को संतुलित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सूरजपुर में आउट ऑफ सिलेबस प्रश्नों को लेकर सामने आया यह मामला अब एक सकारात्मक उदाहरण बन गया है, एक शिक्षक की सजग पहल और प्रशासन की त्वरित कार्रवाई ने यह साबित कर दिया कि छात्र हित सर्वोपरि है, यह घटना न केवल व्यवस्था में सुधार का संकेत देती है, बल्कि भविष्य में ऐसी त्रुटियों से बचने के लिए भी एक सीख के रूप में देखी जा रही है।

प्रश्नपत्र में सामने आई गंभीर त्रुटि

जानकारी के अनुसार, कक्षा चौथी के हिंदी प्रश्नपत्र में कुल 7 अंकों के तीन प्रश्न ऐसे पूछे गए थे, जो निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर थे, इतना ही नहीं, ये प्रश्न छठी-सप्तम भाषा के पाठों से जुड़े थे, जबकि सूरजपुर जिला सरगुजा संभाग में आता है, जहां सरगुजा आधारित पाठ्यक्रम लागू है, इस विचलित के कारण परीक्षा के दौरान छात्रों के बीच भ्रम की स्थिति बनी रही और कई विद्यार्थियों को प्रश्न समझने में कठिनाई हुई, इसका सीधा असर उनके प्रदर्शन पर पड़ने की आशंका जताई गई।

प्रधान पाठक की पहल बनी बदलाव का कारण

इस पूरे मामले को शासकीय प्राथमिक शाला चंद्रखंड के प्रधान पाठक गौतम शर्मा ने



गंभीरता से उठाया, उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी, सूरजपुर को पत्र लिखकर इस त्रुटि की जानकारी दी और छात्रों के हित में तत्काल समाधान की मांग की, उन्होंने अपने पत्र में स्पष्ट किया कि प्रश्नपत्र में शामिल प्रश्न क्षेत्रीय पाठ्यक्रम के अनुरूप नहीं हैं और इससे विद्यार्थियों के साथ अन्याय हो सकता है, साथ ही उन्होंने मूल्यांकन प्रक्रिया को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने की आवश्यकता भी बताई।

जांव में सही पाई गई शिकायत

मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने तुरंत जांच दल गठित किया, जांच के दौरान यह स्पष्ट हो गया कि प्रश्न वास्तव में निर्धारित पाठ्यक्रम और स्वीकृत पाठ्यपुस्तक के अनुरूप नहीं थे, जांच रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि क्षेत्रीय भाषा आधारित पाठ्यक्रम की अनदेखी की गई, जो एक गंभीर शैक्षणिक त्रुटि है।

छात्र हित में 7 बोनस अंक देने का निर्णय

जांच के बाद शिक्षा विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छात्र हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिया, आदेश जारी कर जिले के सभी विद्यार्थियों को संबंधित 7 अंकों को बोनस

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भावना के अनुरूप कदम

विशेषज्ञों के अनुसार, यह निर्णय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भावना के अनुरूप है, जिसमें प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा और स्थानीय भाषा में शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है, ऐसे में क्षेत्रीय पाठ्यक्रम से हटकर प्रश्न पूछे जाना नीतिगत रूप से भी उचित नहीं था, जिसे अब सुधार लिया गया है।

हजारों विद्यार्थियों को मिला सीधा लाभ

इस फैसले से जिले के हजारों छात्रों को सीधा लाभ मिला है, जिन विद्यार्थियों को आउट ऑफ सिलेबस प्रश्नों के कारण नुकसान हो सकता था, अब उनके अंकों में संतुलन आ सकेगा, अभिभावकों का कहना है कि यह निर्णय बच्चों के आत्मविश्वास को बनाए रखने में भी मदद करेगा।

शिक्षकों और अभिभावकों ने की सराहना

प्रधान पाठक गौतम शर्मा की सजगता और शिक्षा विभाग की त्वरित कार्रवाई की जिले भर में सराहना हो रही है, शिक्षकों, अभिभावकों और शिक्षा विशेषज्ञों ने इसे एक सकारात्मक और न्यायसंगत पहल बताया है, लोगों का कहना है कि यदि इसी तरह समय पर समस्याओं का समाधान होता रहा, तो शिक्षा व्यवस्था में विश्वास और मजबूती आएगी।

के रूप में प्रदान करने का निर्देश दिया गया, यह निर्णय न केवल छात्रों को न्याय दिलाने वाला है, बल्कि यह शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में भी अहम कदम माना जा रहा है।

उर्वरकों पर किसानों को दिया गया प्रशिक्षण



—संवाददाता—
बलरामपुर, 21 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)।

कृषि विज्ञान केन्द्र, बलरामपुर में पारंपरिक उत्साह के साथ अन्तर्गत विहार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केवीके में

रासायनिक उर्वरकों के विकल्प विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें किसानों को जैविक खेती के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम में उन्नतशील कृषकों ने बहु-चक्रक भाग लिया। कृषि विज्ञान केन्द्र के प्रमुख डॉ.

जी. के. निगम ने किसानों को मृदा परीक्षण के आधार पर ही उर्वरकों का उपयोग करने तथा संतुलित पोषक तत्वों के साथ जैविक खेती को अपनाने के लिए प्रेरित किया। उपस्थित जनप्रतिनिधियों में जैविक खाद के उपयोग, गोबर खाद, कम्पोस्ट एवं वर्मी कम्पोस्ट जैसे जैविक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने की बात कही। किसानों को उर्वरकों के वैकल्पिक स्रोतों जैसे हरी खाद, नील-हरित शैवाल, अजोला उत्पादन, नैनो यूरिया एवं नैनो डीएपी के उपयोग की जानकारी दी गई। जैव उर्वरकों जैसे राइजोबियम, पीएसबी एवं एजोटोबैक्टर के बारे में विस्तार से बताया गया।

नाम परिवर्तन सूचना

में उज्ज्वल कुमार चौहान, आ० जमुना प्रसाद चौहान, निवासी ग्राम इमलीपार, ठाकुरपुर, पो० राववपुरी, तहसील अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा छ०ग० का यह ईशतहार कराना चाहता हूँ - यह कि, मेरे पुत्र के नाम से जारी आधार कार्ड में मेरे पुत्र का नाम सिविन चौहान SIVIN CHAUHAN नाम दर्ज है जो त्रुटिपूर्ण दर्ज हो गया है।

मेरे पुत्र का वास्तविक नाम जन्म प्रमाण पत्र में सिविन चौहान, SEBIN CHOUHAN दर्ज है, जो सत्य एवं सही है। मेरे पुत्र के आधार कार्ड में दर्ज नाम सिविन चौहान SIVIN CHAUHAN के स्थान पर उसका वास्तविक नाम सिबिन चौहान, SEBIN CHOUHAN उसके आधार कार्ड में दर्ज कराना चाहता हूँ इस संबंध में मैं अपना शपथ-पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ। जिस किसी को आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर अनुविभागीय अधिकारी अम्बिकापुर के समक्ष अपना आपत्ति दर्ज करा सकता है। बाद में आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

स्थान :- अम्बिकापुर
दिनांक :- 17/04/2026
आवेदक
उज्ज्वल कुमार चौहान
इमलीपार, ठाकुरपुर, अम्बिकापुर
जिला-सरगुजा छ०ग०

नाम परिवर्तन सूचना

में बिमला दुबे पत्नी स्वर्गीय हरिशरण दुबे ग्राम सेमरा खुर्द, तहसील प्रतापपुर, जिला सूरजपुर की हूँ यह ईशतहार दर्ज कराना चाहती हूँ कि मेरे आधार कार्ड में त्रुटिपूर्ण विमला अंकित हो गया है जिसे सुधार कर बिमला दुबे पढ़ा जाए। एवं मेरे सभी शासकीय व अशासकीय कार्यों में बिमला दुबे के नाम से जाना व पहचाना जाए। इस संबंध में मैं ईशतहार प्रकाशन कर रही हूँ। जिस किसी को आपत्ति हो तो ईशतहार प्रकाशन के 15 दिवस के अन्दर अपना आपत्ति अनुविभागीय अधिकारी अम्बिकापुर के समक्ष दर्ज करा सकता है। बाद में आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आवेदिका
विमला दुबे
पत्नी स्वर्गीय हरिशरण दुबे
ग्राम सेमरा खुर्द, तहसील प्रतापपुर
जिला सूरजपुर, छ०ग०



भक्ति भाव से सराबोर दिखे श्रद्धालु

अयोध्या के लिए रवाना होते समय श्रद्धालुओं के चेहरों पर उत्साह और आस्था साफ झलक रही थी। राम धुन, भजन और जयघोषों के बीच पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया, श्रद्धालुओं ने इस अवसर के लिए शासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह यात्रा उनके जीवन का एक अविस्मरणीय अनुभव साबित होगी और उन्हें आध्यात्मिक संतोष प्रदान करेगी।

है, जो यात्रा के दौरान सभी व्यवस्थाओं का निरंतर निरीक्षण करेंगे, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जुड़ाव का प्रयास— 'श्री रामलला दर्शन योजना' का उद्देश्य केवल धार्मिक यात्रा कराना नहीं, बल्कि लोगों को भारतीय संस्कृति, आस्था और आध्यात्मिक मूल्यों से जोड़ना भी है, अयोध्या धाम में श्रीरामलला के दर्शन से श्रद्धालुओं के जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार होने की

उम्मीद है, यह योजना राज्य में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की दिशा में भी महत्वपूर्ण पहल के रूप में उभर रही है, मनेन्द्राढ़ से श्रद्धालुओं का यह दल न केवल एक धार्मिक यात्रा पर निकला है, बल्कि यह आस्था, संस्कृति और सामूहिक अनुभव का प्रतीक भी है। शासन की इस पहल से आम नागरिकों को आध्यात्मिक अनुभव का अवसर मिल रहा है, जो उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक हो सकता है।

ईशतहार

रा०ग०क०/.../31-6/2025-26
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक कलीमुखार कुंसी एवं सिद्धीकी कुंसी, उम्र-75 वर्ष, जाति कसाब, निवासी मायापुर, अम्बिकापुर जिला, सरगुजा, द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक श्रीमती अजमेरुन निशा शाह पति इकबाल शाह, जाति फकीर, ग्राम रम्पुर खुर्द, तह. अधिपति की नगर अम्बिकापुर शीट नं 03, मोहला कौआड स्थित नजूल भूमि प्लॉट न्यू 1585/6 रकबा 0.04 एकड़ भूमि को पंजाब वृद्ध पत्र दिनांक 11/03/2026 को खरीदा गया है। अतः आवेदक को पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर क्रेता का नाम दर्तावेज की प्रतिलिपि के साथ आवेदन पत्र के अंतर्गत पंजीकृत कराना चाहिए। धारा 109. 110 छ.ग.भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो वे अपना लिखित दावा / आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 05/05/2026 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक- 21/04/2026 को मेरे न्यायालयीन मुद्रा एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया।

नजूल अधिकारी
अम्बिकापुर
सरगुजा (छ.ग.)
सील

ईशतहार

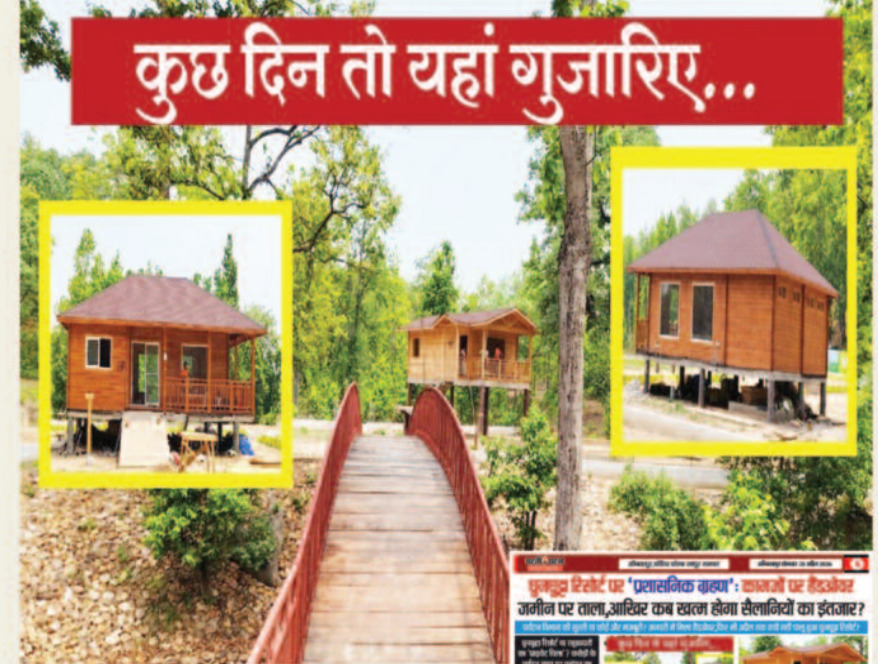
रा०ग०क०/.../31-6/2025-26
एतद द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक अशोक कुमार अम्बट आ.स्व. सन्तन प्रसाद, उम्र- 72 वर्ष, श्रीमती शालनी अम्बट आ० अशोक कुमारी अम्बट, उम्र- 46 वर्ष अन्य वरिष्ठ सभी निवासी केदारपुर पानी टकी नगर निगम अरपुर के द्वारा वतशर का आवेदन प्रस्तुत किया गया है, कि आवेदक का अधिपति की पत्नी एवं माता स्व. श्रीमती बंशला आर्य के स्वामित्व में अधिपति की नगर अम्बिकापुर मोहल्ला केदारपुर शीट नं. 02 स्थित नजूल भूमि खसरा नं. 203/5, 204/3 रकबा क्रमशः 0.03, 0.03 एकड़ एवं शीट नं. 01 पंजाबपार स्थित भूमि खसरा नं. 9/129 रकबा 0.04/3/4 एकड़ भूमि है। भूधारक चर्चा अम्बट की मृत्यु दिनांक 16. 06.2012 को हो गई है। अतः भूधारक की मृत्यु हो जाने उरात उक्त भूमि से उनका नाम खिलीपति कर स्वयं का नाम दर्ज करने हेतु आवेदक का द्वारा मृतक भूधारक के मूल प्रमाण पत्र की छायाप्रति मय दर्तावेज सहित आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 109, 110 छ.ग. भू राजस्व संहिता 1959 के तहत प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो वे अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 05/05/2026 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक-21/04/2026 को मेरे न्यायालयीन मुद्रा एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया।

नजूल अधिकारी
अम्बिकापुर
सरगुजा (छ.ग.)
सील

खबर का असर : घुनघुट्टा रिसोर्ट से हटा 'विभागीय ग्रहण' अब आम जनता के लिए खुले 'ट्री हाउस' के दरवाजे

'ट्री हाउस' पर खत्म हुआ वीआईपी कल्चर, जनता के लिए खुले दरवाजे

- घुनघुट्टा रिसोर्ट विवाद खत्म, अब ऑनलाइन बुकिंग से मिलेगी एंट्री
- सोनहट का घुनघुट्टा रिसोर्ट अब 'प्राइवेट विला' नहीं, पब्लिक डेस्टिनेशन
- वीआईपी कल्चर पर ब्रेक, घुनघुट्टा रिसोर्ट में अब सबका स्वागत
- ऑनलाइन बुकिंग शुरू, अब बिना सिफारिश मिलेगा घुनघुट्टा रिसोर्ट में कमरा
- घुनघुट्टा रिसोर्ट का 'गेट बंद' विवाद खत्म, ट्री हाउस अब सबके लिए
- जनता की आवाज रंग लाई : घुनघुट्टा रिसोर्ट से हटा 'विभागीय ग्रहण'



कुछ दिन तो यहां गुजारिए...



खबर की ताकत और जनदबाव का परिणाम

घुनघुट्टा रिसोर्ट का मामला यह साबित करता है कि मीडिया की सक्रियता, जनप्रतिनिधियों का दबाव और जनता की आवाज मिलकर व्यवस्था को बदलने की ताकत रखते हैं, आज जो रिसोर्ट आम लोगों के लिए खुला है, वह कुछ समय पहले तक केवल चुनिन्दा लोगों तक सीमित था। यह बदलाव केवल प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि जनदबाव और जागरूकता का परिणाम है, अब जरूरत इस बात की है कि इस पारदर्शिता और जनहित की भावना को बनाए रखा जाए और दरों को भी इस तरह संतुलित किया जाए कि हर वर्ग का व्यक्ति इस खूबसूरत 'ट्री हाउस' का अनुभव ले सके, घुनघुट्टा रिसोर्ट अब केवल एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि यह एक उदाहरण बन गया है—कि जब सवाल उठते हैं, तो जवाब भी मिलते हैं।

आदमी वहीं तक पहुंच ही न सके, तो इसका मूल उद्देश्य अधूरा रह जाता है।

—राजन पाण्डेय—
सोनहट/कोरिया, 21 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)।

प्रकृति की गोद में बसे सोनहट क्षेत्र का बहुप्रतीक्षित घुनघुट्टा रिसोर्ट आखिरकार आम जनता के लिए खोल दिया गया है, पिछले कई महीनों से इस रिसोर्ट को लेकर जो विवाद, असमंजस और आरोप-प्रत्यारोप का दौर चल रहा था, वह अब खत्म होता नजर आ रहा है। स्थानीय समाचार-पत्र 'घटती-घटना' में लगातार प्रकाशित खबरों, जनप्रतिनिधियों की सख्त आपत्तियों और जनता की नाराजगी के बाद पर्यटन विभाग हरकत में आया और अब इस रिसोर्ट के 'ट्री हाउस' सहित सभी आवासीय सुविधाओं के लिए ऑनलाइन बुकिंग प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, यह वही रिसोर्ट है जिसे लेकर लंबे समय से यह आरोप लगा रहे थे कि यह केवल रसूखदार लोगों के लिए 'प्राइवेट विला' बनकर रह गया है, जबकि आम पर्यटक गेट से ही लौटा दिए जाते थे, अब जब छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड ने इसकी दूर सार्वजनिक कर दी है और ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा शुरू कर दी है, तो इसे सीधे तौर पर 'खबर का असर' माना जा रहा है।

विवादों के बाद आगे व्यवस्था

घुनघुट्टा रिसोर्ट का निर्माण पर्यटन को बढ़ावा देने और सोनहट क्षेत्र को एक प्रमुख इको-टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से किया गया था, जनवरी 2026 में इसका हैंडओवर होने के बाद उम्मीद की जा रही थी कि यह जल्दी ही पर्यटकों के लिए खुल जाएगा। लेकिन अप्रैल तक भी आम लोगों के लिए इसके दरवाजे बंद रहे, जिससे कई सवाल

खड़े होने लगे, स्थानीय लोगों का आरोप था कि रिसोर्ट में प्रवेश के लिए 'ऊपर' से अनुमति अनिवार्य थी, कई पर्यटक, जो दूर-दूर से यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने पहुंचे, उन्हें गेट से ही वापस कर दिया गया, इस व्यवस्था को लेकर क्षेत्र में नाराजगी बढ़ती गई, राजनीतिक स्तर पर भी यह मुद्दा गरमाया। भाजपा जिलाध्यक्ष देवेन्द्र तिवारी और युथ कांग्रेस अध्यक्ष प्रकाश चन्द्र साहू, अनित दुबे, पुष्पेंद्र राजवाड़े सहित कई नेताओं ने इस मामले को गंभीरता से उठाया। उन्होंने इसे 'तानाशाही संस्कृति' करार देते हुए आम जनता के अधिकारों की अनदेखी बताया, लगातार दबाव और मीडिया की सक्रियता के बाद आखिरकार पर्यटन विभाग को अपनी कार्यप्रणाली में बदलाव करना पड़ा, जिसका परिणाम अब सामने है। सीजन के अनुसार तय की गई दरें-पर्यटन विभाग द्वारा जारी नई गाइडलाइन में रिसोर्ट की दरों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है, जिससे अब पारदर्शिता की उम्मीद बढ़ी है।

प्री-वेडिंग और शूटिंग की सुविधा

पर्यटन को बढ़ावा देने और युवाओं को आकर्षित करने के लिए रिसोर्ट में प्री-वेडिंग शूट और वीडियो शूटिंग की सुविधा भी शुरू की गई है। इसके लिए 15,000 प्रति दिन (जोएसटी सहित) का शुल्क तय किया गया है, इस पैकेज में शूटिंग टीम को दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक दो कमरे 'फ्रेश एंड चेंज' के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे, जो उपलब्धता के आधार पर दिए जाएंगे, हालांकि प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि शूटिंग के दौरान अन्य पर्यटकों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं

नॉन-पीक सीजन (1 अप्रैल - 30 जून)

अवधि में सप्ताह के सभी दिनों के लिए एक समान दरें रखी गई हैं।

- सिंगल ऑक्यूपेंसी: 2100
- डबल ऑक्यूपेंसी: 2625
- अतिरिक्त व्यक्ति के साथ: 3150

पीक सीजन (1 जुलाई - 31 मार्च)

इस अवधि में सप्ताह के दिनों और वीकेंड के हिसाब से दरों में अंतर रखा गया है।

सोमवार से मुरुवार

- सिंगल: 2625
- डबल: 3150
- अतिरिक्त व्यक्ति सहित: 3750

वीकेंड (शुक्रवार, रविवार, रविवार)

- सिंगल: 2835
- डबल: 3360
- अतिरिक्त व्यक्ति सहित: 3885

इन दरों के निर्धारण से यह साफ हो गया है कि रिसोर्ट अब एक व्यवस्थित व्यावसायिक मॉडल के तहत संचालित किया जाएगा, न कि किसी विशेष वर्ग तक सीमित रहेगा।

होनी चाहिए, यदि ऐसा होता है तो संबंधित टीम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मिडिल क्लास की जेब पर भारी पड़ती दरें— हालांकि रिसोर्ट का खुलना एक सकारात्मक कदम है, लेकिन इसकी दरों को

ऑनलाइन बुकिंग से बढ़ी पारदर्शिता

इस पूरे बदलाव का सबसे अहम पहलू है—ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा। अब पर्यटकों को किसी सिफारिश, पहचान या 'ऊपर' के आदेश की जरूरत नहीं पड़ेगी, छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पर्यटक रियल-टाइम में कमरों की उपलब्धता देख सकते हैं, अपनी पसंद के अनुसार बुकिंग कर सकते हैं, डेबिट या क्रेडिट कार्ड से भुगतान कर सकते हैं, इस व्यवस्था से न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि पर्यटन क्षेत्र में भरोसा भी मजबूत होगा। साथ ही, सोनहट क्षेत्र में स्थानीय रोजगार के अवसर भी बढ़ने की उम्मीद है—जैसे गाइड, परिवहन, खान-पान और अन्य सेवाएं।

बिना शोर-शराबे के शुरू हुआ संचालन

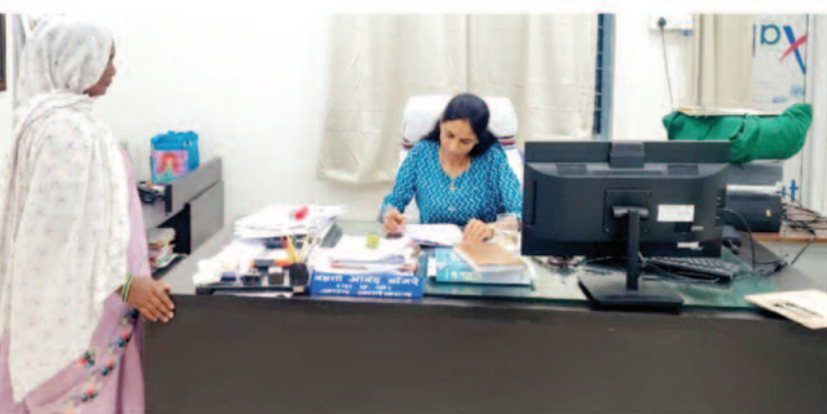
दिलचस्प बात यह रही कि इतने बड़े और बहुप्रतीक्षित प्रोजेक्ट का संचालन बिना किसी औपचारिक उद्घाटन के शुरू कर दिया गया, न कोई फीता कटा, न कोई बड़ा समारोह हुआ और न ही जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया। विभाग ने चुपचाप ऑनलाइन पोर्टल पर बुकिंग शुरू कर दी और रिसोर्ट को आम जनता के लिए खोल दिया, इसे कई लोग इस रूप में देख रहे हैं कि विभाग विवादों से बचना चाहता था या फिर यह सीधे तौर पर मीडिया के दबाव का परिणाम था, जो भी हो, यह साफ है कि यदि खबरें लगातार सामने नहीं आतीं, तो शायद यह रिसोर्ट अभी भी सीमित लोगों तक ही सिमटा रहता।

लेकर आम जनता, खासकर मध्यमवर्गीय परिवारों में असंतोष देखने को मिल रहा है, सोनहट जैसे क्षेत्र में, जहां ज्यादातर पर्यटक आसपास के जिलों से आते हैं और सीमित बजट में घूमने की योजना बनाते हैं, उनके लिए 2600 से 3800 तक का दैनिक किराया काफी महंगा माना जा रहा है, यदि इसमें खाने-पीने, यात्रा और अन्य खर्चों को जोड़ दिया जाए, तो एक दिन का कुल खर्च कई परिवारों के बजट से बाहर हो जाता है। यही कारण है कि स्थानीय लोग मांग कर रहे हैं कि दरों में आंशिक कमी की जाए, स्थानीय

निवासियों के लिए विशेष छूट दी जाए, ऑफ-सीजन में और अधिक किफायती पैकेज उपलब्ध कराए जाएं।

क्या केवल अमीरों तक सीमित रहेगा पर्यटन— यह सवाल अब भी चर्चा में है कि क्या यह रिसोर्ट वास्तव में सभी वर्गों के लिए सुलभ हो पाएगा या फिर केवल संपन्न वर्ग के लिए ही एक प्रीमियम डेस्टिनेशन बनकर रह जाएगा, पर्यटन का उद्देश्य केवल राजस्व कमाना नहीं, बल्कि अधिक से अधिक लोगों को प्राकृतिक और सांस्कृतिक स्थलों से जोड़ना भी होता है, यदि दरें इतनी अधिक हों कि आम

जनदर्शन बना जनविश्वास का मंच, 37 आवेदनों पर हुई सुनवाई



—संवाददाता—
एमसीबी, 21 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)।

कलेक्टर कार्यालय में आयोजित जनदर्शन कार्यक्रम एक बार फिर आम नागरिकों के लिए अपनी समस्याओं को सीधे प्रशासन तक पहुंचाने का प्रभावी मंच बनकर उभरा, कलेक्टर के निर्देशन में आयोजित इस कार्यक्रम में अपर कलेक्टर नम्रता डोंगरे ने जिले के विभिन्न ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों से आए नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उनके त्वरित निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

37 आवेदनों पर हुई सुनवाई

जनदर्शन कार्यक्रम के दौरान कुल 37 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें विभिन्न विभागों से जुड़ी समस्याएं शामिल थीं, नागरिकों ने पारिश्रमिक भुगतान, पेयजल व्यवस्था, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मजदूरी भुगतान, राजस्व प्रकरणों का निराकरण, उत्तराधिकारी प्रमाण-पत्र, भूमि सीमांकन, राशन वितरण, मानदेय भुगतान, अवैध उत्खनन, बैंक कटौती, निर्माण कार्यों के भुगतान, वन अधिकार पत्र, सामाजिक बाजार स्थल परिवर्तन, विद्युत आपूर्ति और ऋण संबंधित मामलों को प्रमुखता से उठाया।

समय-सीमा में निराकरण के निर्देश

अपर कलेक्टर नम्रता डोंगरे ने सभी आवेदनों पर तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित विभागों के

अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक प्रकरण का गंभीरता से परीक्षण कर प्राथमिकता के आधार पर समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाए, उन्होंने स्पष्ट कहा कि आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित और पारदर्शी समाधान प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है, साथ ही अधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ कार्य करने और लंबित मामलों को शीघ्र समाप्त करने के निर्देश भी दिए गए।

नागरिकों को मतकने से मिलेगी राहत

कार्यक्रम के दौरान यह भी जोर दिया गया कि नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें, इसके लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे प्रत्येक प्रकरण का त्वरित निराकरण कर आमजन को राहत प्रदान करें।

प्रशासन और जनता के बीच बढ़ा संवाद

जनदर्शन कार्यक्रम के माध्यम से प्रशासन और आम नागरिकों के बीच सीधा संवाद स्थापित हो रहा है, इससे न केवल समस्याओं के समाधान में तेजी आ रही है, बल्कि शासन के प्रति लोगों का विश्वास भी मजबूत हो रहा है, इस पहल को जिले में सुरासन और पारदर्शिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जहां आमजन की आवाज को प्राथमिकता दी जा रही है।

पारदर्शी वितरण की मांग, आदान सामग्री भंडारण को लेकर कृषि अधिकारी संघ ने सौंपा ज्ञापन

आदान भंडारण को लेकर कृषि अधिकारी संघ का ज्ञापन, समितियों में व्यवस्था की मांग

शासन निर्देशों की अनदेखी पर नाराजगी, कृषि अधिकारियों ने उठाई आवाज
बीज-खाद भंडारण को लेकर संघ सक्रिय, उप संचालक को सौंपा ज्ञापन
वितरण व्यवस्था सुधारने की मांग, सहकारी समितियों को बनाया जाए केंद्र
आदान सामग्री भंडारण पर उठे सवाल, संघ ने दी आंदोलन की चेतावनी
कृषि विभाग में नियमों की अनदेखी? संघ ने सौंपा ज्ञापन



—संवाददाता—
मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, 21 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)।

जिले में कृषि आदान सामग्रियों के भंडारण और वितरण को लेकर एक बार फिर व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं, छत्तीसगढ़ कृषि स्नातक शासकीय कृषि अधिकारी संघ (जिला इकाई-एमसीबी) के प्रतिनिधिमंडल ने उप संचालक कृषि से मुलाकात कर इस संबंध में विस्तृत ज्ञापन सौंपा, ज्ञापन में विभागीय योजनाओं के तहत प्राप्त बीज, उर्वरक और कल्चर के भंडारण को लेकर स्पष्ट व्यवस्था लागू करने की मांग की गई है। कृषि आदान सामग्रियों के भंडारण को लेकर उठे यह मांग सीधे तौर पर किसानों की सुविधा और पारदर्शिता से जुड़ी हुई है, अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस पर कितनी जल्दी और प्रभावी कार्रवाई करता है। यदि मांगें पूरी होती हैं, तो इससे न केवल वितरण व्यवस्था बेहतर होगी, बल्कि किसानों को समय पर संसाधन मिलने से कृषि उत्पादन पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

सहकारी समितियों में भंडारण की मांग—संघ ने मांग रखी कि सभी आदान सामग्रियों का भंडारण विकासखंड कार्यालयों के बजाय अनिवार्य रूप से प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में किया जाए,

उनका कहना है कि सहकारी समितियां ग्रामीण स्तर पर किसानों से सीधे जुड़ी होती हैं, जिससे सामग्री का वितरण अधिक सरल और प्रभावी हो सकता है, संघ के अनुसार, वर्तमान व्यवस्था में कई स्थानों पर सामग्रियों का भंडारण अन्य कार्यालयों में किया जा रहा है, जिससे किसानों को समय पर लाभ नहीं मिल पाता और वितरण प्रक्रिया प्रभावित होती है।

शासन के निर्देशों की अनदेखी पर चिंता—प्रतिनिधिमंडल ने उप संचालक का ध्यान संचालनालय कृषि, रायपुर द्वारा वर्ष 2018 में जारी निर्देशों की ओर आकर्षित किया, इन निर्देशों में स्पष्ट रूप से सहकारी समितियों में भंडारण सुनिश्चित करने की बात कही गई थी, इसके बावजूद कई स्थानों पर इन निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है, जिसे लेकर संघ ने गंभीर चिंता व्यक्त की। उनका कहना है कि नियमों की अनदेखी से न केवल प्रशासनिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, बल्कि किसानों को भी इसका खामियाजा भुगताना पड़ रहा है।

पारदर्शिता और सुविधा बढ़ाने का दावा—संघ का मानना है कि यदि भंडारण सहकारी समितियों में किया जाता है, तो इससे वितरण व्यवस्था अधिक पारदर्शी और सुव्यवस्थित होगी, किसानों को उनके नजदीकी केंद्रों पर समय पर खाद और बीज

उपलब्ध हो सकेगा, जिससे कृषि कार्यों में देरी नहीं होगी, इसके साथ ही सामग्री की सुरक्षा और गुणवत्ता भी बेहतर बनी रहेगी, वर्तमान व्यवस्था में जहां सामग्री के रखरखाव को लेकर कई बार शिकायतें सामने आती हैं, वहीं सहकारी समितियों में बेहतर प्रबंधन की संभावना जताई गई है।

प्रतिनिधिमंडल में चे रहे शामिल—

इस अवसर पर संघ के कई पदाधिकारी उपस्थित रहे, इनमें प्रांतीय कार्यालयीन सचिव एवं जिलाध्यक्ष दीपक कुमार साहू, प्रांतीय प्रतिनिधि आशीष नामदेव, उपाध्यक्ष संजय अमलेरा, जिला सचिव विकास चौरसिया, कोषाध्यक्ष सूरज सिंह भगत और मीडिया प्रभारी रामविहारी लहरें सहित अन्य सदस्य शामिल थे।



कटरीना की जिगरी यार ने किया था आलिया भट्ट को सरेआम ट्रोल, अब दे डाली सफाई

एक अवॉर्ड शो में आलिया भट्ट की होस्टिंग पर कटरीना कैफ की दोस्त ने तंज कसा था। अब उन्होंने इस पर अपनी सफाई दी है।

एक लाइव अवॉर्ड शो होस्ट करने के बाद आलिया भट्ट ट्रोलिंग और चर्चाओं का केंद्र बन गईं। इस आलोचना के बीच, एक्टर और होस्ट मिनी माथुर का एक कमेंट वायरल हो गया, जिसे कई लोगों ने आलिया भट्ट की होस्टिंग पर एक तंज माना। एक कमेंट क्रिएटर की इंस्टाग्राम पोस्ट पर मिनी के कमेंट के बाद यह बात इंटरनेट पर आग की तरह फैल गई। इस घटना के कुछ दिनों बाद, मिनी ने अब आलिया पर तंज कसने के आरोपों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। लेकिन जिस बात ने सबसे ज्यादा हलचल मचाई, वह थी मिनी माथुर का उस इन्फ्लुएंसर की पोस्ट पर किया गया कमेंट। मिनी ने एक सीधा-सादा, लेकिन असरदार कमेंट किया, जिसमें लिखा था, धन्यवाद। आखिरकार किसी ने तो यह बात कही।

मिनी ने दी इस पर सफाई

हालांकि, मिनी ने अब अपना रुख साफ कर दिया है। मीडियो रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने आलिया पर तंज कसने के दावों से इनकार किया और इन अटकलों को बकवास बताया। उन्होंने साफ किया, बिना किसी बात के ही कहानियां गढ़ लेना इंटरनेट का काम है। मैं आपको बताती हूँ कि मैंने यह कमेंट क्यों किया... शो बनाने वाले का इस बात पर एक दिलचस्प नजरिया था कि अवॉर्ड शो वाले एक्टर्स को होस्ट के तौर पर इस्तेमाल करने पर क्यों जोर देते हैं, और फिर बाद में शिकायत करते हैं कि वे उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते। उन्होंने आगे कहा, यह उनकी मुख्य काबिलियत नहीं है, तो फिर उनसे ऐसी उम्मीदें क्यों? यह तो ऐसा है जैसे किसी होस्ट से बंदूक की नोक पर एक्टिंग करने को कहा जाए। मैंने तो बस इसी बात पर कमेंट किया था। जब उनसे पूछा गया कि क्या आलिया के साथ उनकी कोई कथित अनबन है, तो मिनी ने कहा, यह सब बकवास है। मैं आलिया को बहुत पसंद करती हूँ। इसके अलावा मैंने तो वह शो देखा भी नहीं है जिसके बारे में ये लोग इंटरनेट पर बातें कर रहे हैं।

कार्तिक आर्यन बॉलीवुड के पीआर किंग हैं... एक्टर विजय वर्मा ने कसा कार्तिक पर तंज? इंटरनेट पर बवाल

एक्टर विजय वर्मा ने कार्तिक आर्यन को बॉलीवुड का पीआर किंग बताया है, जिससे इंटरनेट पर बहस छिड़ गई है। बॉलीवुड में कार्तिक आर्यन की फिल्मों की चर्चा हो ना हो, लेकिन जनाब लाइमलाइट में जरूर ही रहते हैं। यही वजह है कि कार्तिक आर्यन खूब सुर्खियां बटोरते हैं। सोशल मीडिया पर कार्तिक कभी ट्रोल होते हैं, तो कभी कार्तिक अपनी फिल्मों और स्टाइल के जरिए तारीफें भी पाते हैं और अब लीजिए कार्तिक पर एक एक्टर ने इशारों ही इशारों में कार्तिक पर निशाना साधा है।



कार्तिक की एक्टिंग पर सवाल उठाता है। कार्तिक ने भूल-

नई देवसेना? कयादू लोहार अनुष्का शेट्टी के पूरे समर्पण के रास्ते पर चल रहे...

तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा बहुत कम होता है कि कोई एक ही फिल्म के लिए सालों तक काम करे। पता चला है कि अनुष्का शेट्टी ने पहले अपने करियर के पांच साल बाहुबली जैसे बड़े प्रोजेक्ट के लिए दिए थे। अब, ऐसा लगता है कि यंग एक्ट्रेस कयादू लोहार ने भी इसी तरह का एक बड़ा फैसला लिया है। कयादू लोहार लगभग दो साल से नेचुरल स्टार नानी स्टार पैराडाइज पर काम कर रही हैं, बिना किसी दूसरे प्रोजेक्ट के कमिट किए और पूरा फोकस इसी फिल्म पर कर रही हैं। फिल्मों दुनिया में एक उभरती हुई होरोइज के लिए ऐसा फैसला लेना एक बड़ा रिस्क माना जा रहा है। हाल ही में, कयादू लोहार की कुछ फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट नहीं दिया है। एनालिस्ट्स का कहना है कि ऐसे समय में नए मोकों को छोड़कर सिर्फ एक प्रोजेक्ट पर निर्भर



रही यह फिल्म सफल होती है, तो कयाधु लोहार को बड़ा ब्रेक मिलने की उम्मीद है। दूसरी तरफ, इंडस्ट्री में लगातार फिल्में करना भी एक्ट्रेस के करियर के लिए जरूरी है।

रहना उनके करियर के लिए एक चैलेंज बन सकता है। अगर पैराडाइज- उम्मीद के मुताबिक हिट नहीं होती है, तो हो सकता है कि इसका असर उनके प्युचर पर पड़े। हालांकि, इस फिल्म में कयादू का रोल सिर्फ गैलरी तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि एक्टिंग का भी अच्छा स्कॉप लगता है। खबर है कि उन्हें इमोशनल सीन में अपना टैलेंट दिखाने का अच्छा मौका मिला है। यही वजह है कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट को इतना टाइम दिया है। नानी जैसे टैलेंटेड एक्टर के साथ स्क्रीन शेयर करना भी कयाधु के करियर के लिए प्लस पॉइंट होने की उम्मीद है। अगर पैराडाइज लेवल पर बन कर ही यह फिल्म सफल होती है, तो कयाधु लोहार को बड़ा ब्रेक मिलने की उम्मीद है। दूसरी तरफ, इंडस्ट्री में लगातार फिल्में करना भी एक्ट्रेस के करियर के लिए जरूरी है।

भुलैया सीरीज के दो पार्ट्स में अक्षय कुमार को रिप्लेस किया है, ऐसे में कुछ लोग इससे खफा भी हुए हैं। अब लीजिए हाल ही में कार्तिक को लेकर एक्टर विजय वर्मा ने कहा है कि वो पीआर के किंग हैं। दरअसल हाल ही में एक्टर विजय वर्मा का एक वीडियो रीडिट पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें एक्टर से पूछा गया कि बॉलीवुड में कौन पीआर का किंग है तो इस पर विजय ने झट से कार्तिक आर्यन का नाम ले लिया। मतलब यह है कि बॉलीवुड में अपनी फिल्मों और इमेज को प्रमोट करने में सबसे माहिर कौन है, तो इसमें विजय ने कार्तिक का नाम लिया और इसीलिए उन्होंने कहा है कि इसके लिए कार्तिक पीआर एजेंसी का सहारा लेते हैं।

राका के लिए अल्लू अर्जुन हैदराबाद छोड़ मुंबई में बसाएंगे अपना नया आशियाना?

अल्लू अर्जुन को लेकर यह खबर आ रही थी कि वह फिल्म राका की वजह से मुंबई में शिफ्ट होने वाले हैं, जिससे प्रेनेट दीपिका पादुकोण को भी राहत मिल सकती है। बॉलीवुड की टॉप अभिनेत्री दीपिका पादुकोण इस वक अपनी जिंदगी के सबसे खुबसूरत फेज से गुजर रही हैं। बीते दिनों ही बाजीराव-मस्तानी एक्ट्रेस ने अपनी दूसरी प्रेनेसी की घोषणा की थी, जिसके बाद से ही फैंस उन्हें सोशल मीडिया पर लगातार बधाइयां दे रहे हैं। इसी बीच, इंटरनेट गलियारों में तेजी से यह खबर फैलने लगी कि दीपिका पादुकोण की प्रेनेसी को ध्यान में रखते हुए और फिल्म के सख्त शूटिंग शेड्यूल की मांगों को पूरा करने के लिए साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन हैदराबाद छोड़कर मुंबई शिफ्ट हो रहे हैं। क्या सच में अल्लू अर्जुन राका के लिए मुंबई में अपना नया आशियाना बसाएंगे? आइए नीचे विस्तार से जानते हैं इसकी सच्चाई- **तथा राका के लिए मुंबई शिफ्ट होंगे अल्लू अर्जुन?**

अल्लू अर्जुन के मुंबई शिफ्ट होने की इन अफवाहों पर अब एक्टर के करीबी सूत्र ने चुप्पी तोड़ी है। डेक्कन क्रॉनिकल की रिपोर्ट के मुताबिक, सूत्र ने बताया, वह खुश हैं और हैदराबाद में पूरी तरह से सेटल और कंपर्टबल हैं। वह अपने शहर से बहुत ज्यादा गहराई से जुड़े हुए हैं। उनके मुंबई शिफ्ट होने की इन खबरों में रही भर भी सच्चाई नहीं है। दरअसल, बीते दिनों यह खबर सामने आई थी कि अल्लू अर्जुन अपने व्यक्तिगत और पेशेवर कारणों से कुछ समय के लिए मुंबई शिफ्ट हो सकते हैं। अफवाहों में दावा किया गया था कि फिल्म के लिए कड़ी तैयारी, सख्त शूटिंग शेड्यूल और लंबी प्रोडक्शन टाइमलाइन की मांगों को पूरा करने के लिए अल्लू ने यह फैसला लिया है। वह बार-बार शहरों के बीच यात्रा करने से बचना चाहते हैं। यह भी कहा जा रहा था कि उनके मुंबई आने के इस कथित फैसले से प्रेनेट दीपिका पादुकोण को भी बड़ी राहत मिलती। हालांकि, पृष्ठा 2 एक्टर के करीबी सूत्रों ने अब इस खबर को सिर से खारिज कर दिया है।

दीपिका पादुकोण का शूटिंग शेड्यूल है सेम रिपोर्ट्स के मुताबिक, अभिनेत्री दीपिका पादुकोण भले ही गर्भवती हैं, लेकिन उनके शूटिंग शेड्यूल में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। वह तय शेड्यूल के मुताबिक ही अपना काम करेंगी। अगर अल्लू अर्जुन मुंबई आते, तो दीपिका को शूटिंग के लिए दूसरे शहरों में सफर नहीं करना पड़ता और उनके लिए काम करना काफी आसान हो जाता, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं हो रहा है।

सनी देओल और इमरान हाशमी फिर से भिड़ेंगे

2026 में आने वाला इंडियन डे वीकेंड हाल के बॉलीवुड इतिहास के सबसे बड़े सिनेमाई शोअउन में से एक बनने वाला है। एक रेजर हिस्ट्री रिपोर्टर इट्स स्ट्रस मोमेंट में, इंडस्ट्री के बड़े स्टार सनी देओल और इमरान हाशमी साल के दो सबसे ज्यादा इंतजार किए जाने वाले प्रोजेक्ट्स के साथ बॉक्स ऑफिस पर आमने-सामने आने के लिए तैयार हैं।

शिवम की वापसी: आवारापन 2

विशेष फिल्मस ने 14 अगस्त, 2026 को 'आवारापन 2' की रिलीज अनाउंसमेंट करके ऑफिशियली हवा बूझ दी है। 2007 की कल्ट क्लासिक का सीकवल, जिसने इमरान हाशमी के 'सिरियल किस्' परा को थोड़ी दिल को छू लेने वाली ट्रेजेडी के टच के साथ डिफाइन किया, इस दूसरे इंस्टॉलमेंट में हाशमी शिवम के अपने आइकॉनिक रोल को रिपीट करते हुए दिख रहे हैं। नितिन कक्कर (फिलिपिस्तान फेम) के डायरेक्शन और विशेष भूट के प्रोड्यूसर में, इस फिल्म में दिशा पटानी फीमेल लीड के तौर पर हैं। ऑरिजिनल एक जबरदस्त एक्शन-ड्रामा थी जो अपने जबरदस्त प्रीतम साउंडट्रैक के लिए जानी जाती थी, लेकिन सीकवल को बहुत बड़े लेवल पर इंटेंस म्यूजिकल लव स्टोरी के तौर पर रेशा किया जा रहा है। फैंस पहले से ही इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या नया म्यूजिकल पहली फिल्म की डिस्कोग्राफी के लेजेंडरी स्टेटस को बनाए रख पाएगा।

द पीरियड पावरहाउस : लाहौर 1947

दूसरी तरफ सनी देओल लाहौर 1947 के साथ हैं, जो 13 अगस्त, 2026 को रिलीज होने वाली है, यानी हॉलिडे वीकेंड शुरू होने से ठीक एक दिन पहले। यह प्रोजेक्ट एक बड़ा कोलेबोरेशन है, जिसमें इंडियन सिनेमा के तीन बड़े नाम एक साथ आ रहे हैं- लीड रोल में सनी देओल। डायरेक्टर के तौर पर राजकुमार संतोषी। आमीर खान प्रोडक्शंस के तहत प्रोड्यूसर के तौर पर आमीर खान। गदर 2 और बाँदर 2 की रिकॉर्ड तोड़ सफलता के बाद, देशभक्ति वाले पीरियड ड्रामा जॉर्न में सनी देओल की वापसी से भारी भीड़ आने की उम्मीद है। फिल्म में प्रीति जिंटा और शबाना अजमी जैसे शानदार सपोर्टिंग कास्ट भी हैं, और ए.आर. रहमान का म्यूजिकल स्कोर है। **19 साल पुराना रंजिश का मैच**
इस क्लैश को जो चीज सच में दिलचस्प बनाती है, वह है इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्ट। ठीक 19 साल पहले, 29 जून, 2007 को, इन दोनों स्टार्स के बीच भी ऐसी ही लड़ाई हुई थी : 2007: सनी देओल की फैमिली ड्रामा अपने का मुकाबला इमरान हाशमी की आवारापन से हुआ। नतीजा : उस समय, अपने कमर्शियल विनर बनी, जबकि आवारापन ने डिफ्ट विंडो पर अच्छा परफॉर्म नहीं किया, और सालों बाद हमें मीडिया और स्ट्रीमिंग पर इसे कल्ट स्टेटस मिला।



नीतू चंद्रा इमोशनल गहराई के साथ आखिरी सवाल के लिए एकदम सही

एक्टर नीतू चंद्रा हमेशा से आने वाली फिल्म आखिरी सवाल के लिए पहली पसंद थीं, जैसा कि प्रोजेक्ट से जुड़े सूत्रों ने कन्फर्म किया है। इस फिल्म में संजय दत्त लीड रोल में हैं, इसे अभिजीत मोहन वारंग ने डायरेक्ट किया है और यह आरएसएस (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) के 100 साल के सफर पर आधारित है। प्रोडक्शन से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, मेकर्स शुरू से ही इस रोल के लिए नीतू चंद्रा को कास्ट करने को लेकर क्लियर थे। इस कैरेक्टर के लिए इमोशनल गहराई और संयम का एक अनोखा मिक्स चाहिए था, ये खूबियां टीम को उनके एक्टिंग स्टाइल से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई लगती थीं। शुरू में इस कैरिअर ने उनके सिलेक्शन को प्रोजेक्ट के लिए एक जरूरी क्रिएटिव फैसला बना दिया। इनसाइडर्स का यह भी कहना है कि उनके शामिल होने से फिल्म की कहानी में एक खास वजन आता है, जिसमें इंटेंस इमोशंस और लेंथी स्टोरीटेलिंग पर फोकस करने की बात कही गई है। उनके होने से फिल्म के टोन को कॉम्प्लेंट करने और कहानी के ओवरऑल इम्पैक्ट को बढ़ाने की उम्मीद है। हालांकि आखिरी सवाल के बारे में और डिटेल्स अभी सीक्रेट हैं, लेकिन कास्टिंग चॉइस से पता चलता है कि फिल्म का मेकसद परफॉर्मंस पर आधारित कहानी देना है। संजय दत्त इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं और नीतू चंद्रा इसमें अहम रोल निभा रही हैं, इसलिए यह फिल्म देखने लायक बन रही है। नमाशी चक्रवर्ती, मुग़ाल कूलकर्णी, त्रिधा चौधरी, अर्चना अय्यर और भी कई कलाकारों वाली आखिरी सवाल 8 मई को थिएटर में रिलीज होगी।



खेल समाचार

ताशकंद 2027 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा

नई दिल्ली, 21 अप्रैल 2026। ताशकंद को 2027 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के होस्ट शहर के तौर पर कन्फर्म किया गया है। यह पहली बार है जब यह मशरूफ कॉम्पिटिशन उज्बेकिस्तान और बड़े सेंट्रल एशियाई इलाके में होगा। यह अनाउंसमेंट वल्टेड पैरा एथलेटिक्स ने की, जिसने कन्फर्म किया कि दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल पैरा-स्पोर्ट इवेंट जून 2027 में ओलंपिक सिटी मेन स्टेडियम में होगा, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स वेबसाइट के मुताबिक। ताशकंद 2027 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का 13वां एडिशन होगा और यह इवेंट एशिया में होस्ट किया जाएगा, इससे पहले दोह 2015, दुबई 2019, कोबे 2024 और नई दिल्ली 2025 में यह इवेंट हो चुका है। 100 से ज्यादा देशों के लगभग 1,300 एथलीटों के हिस्सा लेने की उम्मीद के साथ, यह चैंपियनशिप देश में अब तक का सबसे बड़ा इंटरनेशनल पैरा स्पोर्ट इवेंट के लिए तैयार है। हालांकि इवेंट्स की आखिरी संख्या अभी कन्फर्म नहीं हुई है, लेकिन प्रोग्राम में कम से कम 16 खिंडर होंगे, जो पैरालंपिक गैम्स प्रोग्राम के साथ जुड़े होंगे, और इसमें और भी इवेंट्स होने की संभावना है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स के हेड डॉल फिट्ज़गैराल्ड ने इस घोषणा का स्वागत किया और देश और इलाके दोनों के लिए इस इवेंट की अहमियत बताई।

इटली के पूर्व स्टार का गार्डियोला को समर्थन
मैड्रिड, 21 अप्रैल 2026। इटली और जुवेंटस के पूर्व डिफेंडर लियोनार्डो बोनुची ने मैनेज्मेन्ट सिटी के पेप गार्डियोला को नेशनल टीम का हेड कोच बनाने और अजुरी के लगातार तीसरी बार फीफा वर्ल्ड कप के लिए इटालीफाई न कर पाने के बाद, बड़ा बदलाव लाने की मांग की है। अप्रैल की शुरुआत में एक चौंकाने वाली बात यह हुई कि इटली लगातार तीसरे फीफा डब्ल्यूसी में जगह बनाने में नाकाम रहा, जब उसे ब्राज़ील और अर्जेंटीना से पेनल्टी में 4-1 से हार का सामना करना पड़ा। चार बार के चैंपियन, जिन्होंने आखिरी बार 2006 में वर्ल्ड कप जीता था और आखिरी बार 2014 में इस बड़े टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था, वर्ल्ड कप में 48 टीमों के शामिल होने के बावजूद एक बार फिर फूटबॉल की कुछ बेहतरीन टीमों के साथ मुकाबला करने से चूक गए। यह टूर्नामेंट 11 जून से 19 जुलाई तक होगा और इसे यूएसए मैक्सिको और कनाडा मिलकर होस्ट करेंगे।

नई दिल्ली, 21 अप्रैल 2026। ताशकंद को 2027 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के होस्ट शहर के तौर पर कन्फर्म किया गया है। यह पहली बार है जब यह मशरूफ कॉम्पिटिशन उज्बेकिस्तान और बड़े सेंट्रल एशियाई इलाके में होगा। यह अनाउंसमेंट वल्टेड पैरा एथलेटिक्स ने की, जिसने कन्फर्म किया कि दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल पैरा-स्पोर्ट इवेंट जून 2027 में ओलंपिक सिटी मेन स्टेडियम में होगा, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स वेबसाइट के मुताबिक। ताशकंद 2027 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का 13वां एडिशन होगा और यह इवेंट एशिया में होस्ट किया जाएगा, इससे पहले दोह 2015, दुबई 2019, कोबे 2024 और नई दिल्ली 2025 में यह इवेंट हो चुका है। 100 से ज्यादा देशों के लगभग 1,300 एथलीटों के हिस्सा लेने की उम्मीद के साथ, यह चैंपियनशिप देश में अब तक का सबसे बड़ा इंटरनेशनल पैरा स्पोर्ट इवेंट के लिए तैयार है। हालांकि इवेंट्स की आखिरी संख्या अभी कन्फर्म नहीं हुई है, लेकिन प्रोग्राम में कम से कम 16 खिंडर होंगे, जो पैरालंपिक गैम्स प्रोग्राम के साथ जुड़े होंगे, और इसमें और भी इवेंट्स होने की संभावना है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स के हेड डॉल फिट्ज़गैराल्ड ने इस घोषणा का स्वागत किया और देश और इलाके दोनों के लिए इस इवेंट की अहमियत बताई।

देवदत्त पडिकवल, आकिब नबी और ये 2 खिलाड़ी, टीम इंडिया के लिए खेलेंगे टेस्ट?

टीम इंडिया को अफगानिस्तान के खिलाफ एक टेस्ट मैच खेलना है... इस मैच में सेलेक्टर्स सीनियर खिलाड़ियों को रेस्ट देकर टीम के युवा खिलाड़ियों को आजमा सकते हैं...

नई दिल्ली, 21 अप्रैल 2026। जून में अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाले एकमात्र टेस्ट मैच के लिए भारतीय चयन समिति घरेलू क्रिकेट के चमकते सितारों को मौका देने पर विचार कर रही है। आईपीएल 2026 के फाइनल और इस टेस्ट के बीच समय काफी कम है और चूंकि यह मुकाबला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है, इसलिए सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया जाना लगभग तय है। ऐसे में टीम इंडिया की बेंच स्ट्रेंथ को आजमाने का यह सबसे सही मंच साबित हो सकता है।



इन खिलाड़ियों की हो सकती है एंट्री
सीनियर खिलाड़ियों की गैरमौजूदगी में देवदत्त पडिकवल, गुरनूर बरार, आकिब नबी और मानव सुथार जैसे खिलाड़ियों की किस्मत चमक सकती है। इन युवाओं ने घरेलू सत्र में लगातार प्रभावित किया है। चयन समिति का मानना है कि जिन मुकाबलों से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पाईंट्स नहीं मिलने हैं, वहां स्टाफ प्लेयर्स को थकाने का कोई मतलब नहीं है। एक सूत्र ने कहा, इस चयन समिति की एक बात साफ है कि वे जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेते। गुरनूर, मानव, हर्ष दुबे, आकिब और देवदत्त पडिकवल ने अपनी खेल से सभी का ध्यान खींचा है। अब सब कुछ टीम मैनेजमेंट और मेडिकल टीम की चर्चा पर निर्भर करेगा क्योंकि संसाधनों का सही इस्तेमाल ही प्राथमिकता है।

स्टार खिलाड़ियों को दिया जाएगा रेस्ट
भारतीय कप्तान शुभमन गिल पहले भी वर्कलोड मैनेजमेंट और फॉर्मेट बदलने के बीच मिलने वाले कम समय को लेकर चिंता जता चुके हैं। जून का शेड्यूल काफी व्यस्त है जिसमें टेस्ट के तुरंत बाद तीन वनडे और फिर आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज होगी है। इसी वजह से जसप्रीत बुमराह, केएल राहुल और रविंद्र जडेजा जैसे ऑल राउंडर खिलाड़ियों को टेस्ट से ब्रेक देकर सीधे वनडे सीरीज में उतारा जा सकता है।

लगातार खेलनी है टीम को सीरीज
शेड्यूल की चुनौतियों पर सूत्र ने आगे बताया, टेस्ट और वनडे सीरीज के बीच तैयारी का वक बहुत कम है। अगर गिल, बुमराह या राहुल जैसे खिलाड़ी तीनों सीरीज खेलते हैं तो उन्हें एक महीने के भीतर टी20 से टेस्ट और फिर वनडे फॉर्मेट में ढलना होगा। कप्तान और कोच पहले भी ऐसे बिजौ शेड्यूल पर अपनी आवाज उठा चुके हैं इसलिए अंतिम फैसला उन्हीं की राय पर टिका होगा।

तिलक वर्मा के शतक से मुंबई इंडियंस ने गुजरात टाइटन्स को हराया

नई दिल्ली, 21 अप्रैल 2026। तिलक वर्मा ने इंडियन प्रीमियर लीग में शानदार पहली सेंचुरी लगाकर फॉर्म में वापसी की, जिससे मुंबई इंडियंस ने सोमवार को गुजरात टाइटन्स को 99 रन से हराकर लगातार चार मैच हारने का सिलसिला तोड़ा। तिलक 45 गेंदों पर 101 रन बनाकर नॉट आउट रहे, और पारी की आखिरी गेंद पर चौका लगाकर एमआई को खराब शुरुआत के बाद पांच विकेट पर 199 रन तक पहुंचाया। जवाब में, जीटी 15.5 ओवर में 100 रन पर आउट हो गईं, जिसमें बार्ने हथक के सीमर अधिनी कुरनर ने चार ओवर में 4/24 के शानदार आंकड़े दिए। पहले बॉलिंग करने के लिए कर्नर पर, एमआई मुश्किल में पड़ गई जब कर्गिसे रबाडा (4 ओवर में 3/33) ने पावरप्ले में तीन विकेट लिए। नमन धीर और 32 गेंदों पर 45 रन बनाए, लेकिन तिलक ने एमआई के लिए बड़ा काम किया, सात छक्के और आठ चौके लगाकर लीग के शुरुआती दौर में खराब स्कोर का सिलसिला खत किया।



इंग्लैंड महिला टीम चयन को लेकर कोच का बयान
लंदन, 21 अप्रैल 2026। शार्लेट एडवर्ड्स ने माना कि आने वाले विमेंस टी 20 वर्ल्ड कप के लिए इंग्लैंड की टीम चुनना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि अब टीम में काफी टैलेंट है, और कई खिलाड़ी लगातार हाई लेवल पर परफॉर्म कर रहे हैं। एडवर्ड्स ने कहा कि इससे सिलेक्शन का काम चैलेंजिंग तो है, लेकिन यह एक पॉजिटिव बात भी है, क्योंकि इससे पता चलता है कि टीम ने पिछले कुछ सालों में कितना सुधार किया है और कहा कि वह वर्ल्ड कप में जाने से पहले कमजोर खिलाड़ियों के बजाय मुश्किल सिलेक्शन फैसलों का सामना करना पसंद करेंगी। आईसी विमेंस टी 20 वर्ल्ड कप का दसवां एडिशन आने वाला है, जिसमें 12 टीमों होंगी, जिससे यह अब तक का सबसे बड़ा



विमेंस टी 20 वर्ल्ड कप बन जाएगा। टूर्नामेंट 12 जून से शुरू होगा, और विनर का ताज 5 जुलाई को फाइनल में पहनाया जाएगा। टूर्नामेंट की शुरुआत मेजबान इंग्लैंड की टीम एजबेस्टन में श्रीलंका से खेलेंगी, और ग्रुप स्टेज के मैच 28 जून को खत्म होंगे। पहला और दूसरा सेमी-फाइनल 30 जून और 2 जुलाई को दो ओवल में खेले जाएंगे, और उसके बाद लाईंस में फाइनल होगा।

27 अप्रैल को विधानसभा का विशेष सत्र महिला आरक्षण बिल पर सरकार लाएगी निंदा प्रस्ताव

रायपुर, 21 अप्रैल 2026। छत्तीसगढ़ विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र 27 अप्रैल को होगा। इस सत्र में राज्य सरकार महिला आरक्षण कानून और डीलिटिमेंशन से जुड़े 131वें संवैधानिक संशोधन विधेयक के पास नहीं होने के विरोध में निंदा प्रस्ताव लाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि वे 'दुखी मन' से अपनी बात रख रहे हैं। उनके मुताबिक महिलाओं को 33% आरक्षण देने का सपना विपक्ष के रवैये के कारण पूरा नहीं हो पाया।

महिलाओं की उम्मीदों को टैट

सीएम साय ने कहा कि इस फैसले से देश की करोड़ों महिलाओं की उम्मीदों को टैट पहुंची है। उनका मानना है कि यह सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि महिलाओं के अधिकारों से जुड़ा मामला है।



छत्तीसगढ़ का उदाहरण दिया

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को करीब 57% आरक्षण दिया गया है। वहीं विधानसभा में भी 20% से ज्यादा महिला विधायक हैं। इससे साफ है कि सरकार महिला सशक्तिकरण को लेकर गंभीर है।

विपक्ष पर आरोप

साय ने विपक्ष पर समाज को बांटने की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस तरह की राजनीति से देश को नुकसान होता है।

आगे भी उठेंगे कदम

मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि महिला आरक्षण को लेकर आगे सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जनता इस मुद्दे को समझ रही है और समय आने पर सही फैसला करेगी।

रात्र रहेगा अग्रिम

27 अप्रैल का यह विशेष सत्र राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है। महिला आरक्षण जैसे मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस हो सकती है।

छत्तीसगढ़ में बदला राशन दुकान खुलने का टाइम, अब सुबह 7 से रात 9 बजे तक मिलेंगे अनाज

रायपुर, 21 अप्रैल 2026। छत्तीसगढ़ में बढ़ती भीषण गर्मी के बीच आम लोगों को राहत देने के लिए खाद्य विभाग ने उचित मूल्य की राशन दुकानों के समय में बदलाव किया है। अब सभी राशन दुकानों में सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक खुली रहेंगी, ताकि हितग्राही तेज धूप से बचते हुए सुविधाजनक समय पर राशन ले सकें।

विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने राशन दुकानों को दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक आवश्यकतानुसार बंद रखा जा सकता है। यह निर्णय दुकानदारों और कर्मचारियों को भी गर्मी से राहत देने के लिए लिया गया है। इस बार खास व्यवस्था यह की गई है कि राशन दुकानों में सोमवार, रविवार और अन्य सरकारी छुट्टियों के दिन भी खुली रहेंगी। इन दिनों में भी नियमित रूप से अनाज का वितरण किया जाएगा, ताकि किसी भी हितग्राही को परेशानी न हो। बता दें कि प्रदेश में वर्तमान में तीन माह का चावल



की समस्या सामने आ रही है, लेकिन विभाग का कहना है कि इसे जल्द ही दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। अपूर्ति को नियमित और सुचारु बनाए रखने के लिए लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है।

महिला आरक्षण बिल के पारित नहीं होने पर भाजपा का गुस्सा बरकरार ऐतिहासिक गलती के लिए छत्तीसगढ़ की महिलाएं कांग्रेस को कभी नहीं करेंगी माफ : उप मुख्यमंत्री साव

रायपुर, 21 अप्रैल 2026। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लोकसभा में पारित नहीं हो पाने से पहले ही भाजपा नेताओं का गुस्से पर आज छत्तीसगढ़ पहुंची कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन के बयान ने आग में भी छालने का काम किया। यह गुस्सा उप मुख्यमंत्री अरुण साव के बयान में साफ नजर आया, जब उन्होंने बिल पारित होने को कांग्रेस की ऐतिहासिक गलती करार देते हुए कहा कि इसके लिए छत्तीसगढ़ की महिलाएं कभी माफ नहीं करेंगी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने रायपुर के न्यू सर्किट हॉस में प्रचारकों से नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लोकसभा में पारित नहीं हो पाने पर कहा कि वास्तव में देश की आधी आबादी के साथ अन्याय और धोखा हुआ है। दशकों तक नारी शक्ति को उनके अधिकार से वंचित किया गया है। जब नगरीय निकायों एवं पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण मिला हुआ है, तो उन्हें विधानसभा और



लोकसभा में आरक्षण क्यों नहीं मिलना चाहिए? उन्होंने कहा कि कांग्रेस और विपक्षी दलों ने पिछले चार दशकों से महिलाओं को उनके अधिकार से वंचित रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने प्रयत्न किया कि आधी आबादी को उनका अधिकार मिले, लेकिन कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने षड्यंत्र करके नारी शक्ति को फिर से उनके अधिकार से वंचित किया है। उनकी आवाज को और बुलंद करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। उप

महासमुंद में पकड़ाया 46 लाख का चांदी ओडिशा से आ रहे बस यात्री से बरामद हुई ज्वेलरी, वैध दस्तावेज नहीं, आभूषण जब्त

महासमुंद, 21 अप्रैल 2026। महासमुंद जिले में अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत सिंगोड़ा पुलिस ने 46 लाख रुपये से अधिक कीमत के चांदी के आभूषण जब्त किए हैं। यह कार्रवाई नेशनल हाईवे के 53 रेहटीखोल चेक पोस्ट पर की गई, जहां एक यात्री के पास से करीब 18.590 किलोग्राम चांदी के गहने बरामद हुए। पुलिस ने ओडिशा की ओर से आ रही 'श्री श्याम ट्रेवलर्स' की एक बस को रेहटीखोल चेक पोस्ट पर रोका। वाहनों की जांच के दौरान, एक यात्री के पास मौजूद बैग सदिग्ध लगा, जिसके बाद उसकी तलाशी ली गई।



सोमवर्ती क्षेत्रों में चलाया जा रहा सघन चेकिंग अभियान : मामले की गंभीरता को देखते हुए, जब्त सामग्री की जानकारी आयरक विभाग और राजस्व को धारा 94 बी.एन.एस. के तहत नोटिस जारी किया गया। यात्री द्वारा लिखित में दस्तावेज न होने की जानकारी देने पर पुलिस ने धारा 106 के तहत चांदी के आभूषणों को जब्त कर लिया।

कार्रवाई के लिए भेज दी गई है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले में अवैध परिवहन और गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। यह कार्रवाई इसी अभियान का एक हिस्सा है। एक महीने पहले भी पकड़े गए थे 54 लाख के चांदी के आभूषण : इस से पहले भी महासमुंद के कोमाखान में तलाशी के दौरान कार को बीच वाली सीट पर रखे तीन बैगों में 10 प्लास्टिक डिब्बों में पैक कुल 41 पैकेट चांदी के फेंसी आभूषण मिले थे। जब्त किए गए आभूषणों का वजन 54 लाख 60 हजार रुपये बताई गई थी। कार में सवार व्यक्तियों ने अपनी पहचान टिकरा कुमार साहू (38), निवासी बाना, थाना उरला, जिला रायपुर और विरेन्द्र प्रधान (50), निवासी मठपारा, थाना टिकरापारा, जिला रायपुर के रूप में बताई थी। पछताछ में उन्होंने बताया कि वे इन आभूषणों को ओडिशा से रायपुर ले जा रहे थे। हालांकि, वे इन आभूषणों से संबंधित कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए थे।

पीडब्ल्यूडी ब्रिज की गिर में गर्दन फंसने से बुजुर्ग की मौत, पुलिस जांच में जुटी

रायपुर, 21 अप्रैल 2026। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के राजेंद्र नगर इलाके में एक चौकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक बुजुर्ग की सदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पीडब्ल्यूडी ब्रिज के पास डिवाइडर की लोहे की ग्रिल में उनकी गर्दन फंसी मिली, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान परशुराम नगर पुरेना निवासी 80 वर्षीय जगदीश प्रसाद के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वे रोज की तरह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। सोमवार दोपहर करीब 1:30 बजे राहगीरों की नजर उन पर पड़ी, जब उनकी गर्दन ग्रिल में फंसी हुई थी और वे बेहोश हालत में थे। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और प्रशासन की मदद से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक जांचकारियों के अनुसार, ग्रिल में गर्दन फंसने से ही उनकी मौत हो गई। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर उनकी गर्दन ग्रिल में फंसी कैसे? यह हादसा है, आमहत्या या फिर कोई और कारण, फिलहाल स्थिति स्पष्ट नहीं है। पुलिस ने मार्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। राजेंद्र नगर थाना प्रभारी के मुताबिक आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह सामने आ पाएगी।



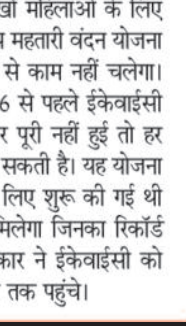
मेडिकल रिपोर्ट निगेटिव होने के बावजूद पीड़ित बच्ची की गवाही पर आरोपी को उल्टा कैद

बिलासपुर, 21 अप्रैल 2026। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सात साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए निचली अदालत द्वारा सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि पीड़िता की गवाही स्पष्ट, सुसंगत और विश्वसनीय है, तो केवल मेडिकल या वैज्ञानिक साक्ष्य के अभाव या निगेटिव होने के आधार पर आरोपी को बरी नहीं किया जा सकता। जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने आरोपी की अपील पर सुनवाई करते हुए यह ऐतिहासिक टिप्पणी की। मामले में आरोपी ने अपनी सजा को चुनौती दी थी और तर्क दिया था कि मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए उसे बरी किया जाना चाहिए।



महतारी वंदन योजना पर बड़ा अलर्ट, 30 जून है आखिरी तारीख

रायपुर, 21 अप्रैल 2026। छत्तीसगढ़ की लाखों महिलाओं के लिए एक बहुत जरूरी खबर सामने आई है। अगर आप महतारी वंदन योजना का लाभ ले रही हैं तो अब सिर्फ इंतजार करने से काम नहीं चलेगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि 30 जून 2026 से पहले इंकेवाइसी कराना अनिवार्य है। अगर यह प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं हुई तो हर महीने मिलने वाली 1000 रुपये की किस्त रुक सकती है। यह योजना राज्य की महिलाओं को आर्थिक सहारा देने के लिए शुरू की गई थी लेकिन अब लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जिनका रिकॉर्ड पूरी तरह सही और अपडेट होगा। इसलिए सरकार ने इंकेवाइसी को जरूरी कर दिया है ताकि सही लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे।



धमतरी में 72 लाख का गांजा जब्त, दो तस्कर गिरफ्तार ओडिशा से महाराष्ट्र ले जा रहे थे, वन विभाग ने चेकिंग के दौरान कार से पकड़ा

धमतरी, 21 अप्रैल 2026। छत्तीसगढ़ के धमतरी में वन विभाग और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 127 किलो से अधिक गांजा जब्त किया है। इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जो ओडिशा से महाराष्ट्र गांजा ले जा रहे थे। जब्त किए गए गांजे और अन्य सामान की कुल कीमत 72 लाख रुपये से अधिक बताई जा रही है। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। यह कार्रवाई 20 अप्रैल की शाम धमतरी जिले के सिहावा थाना क्षेत्र में हुई। सफरार्थ फॉरेस्ट नाका पर वन विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों ने नियमित चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान एक सदिग्ध कार को डिटो रेंजर ने रोका और उसकी तलाशी ली।

कार की डिवकी से 127 किलो गांजा बरामद तलाशी के दौरान कार की डिवकी में भूरे रंग के सेलो टेप से पैक किए गए 62 पैकेट गांजा मिला। वाहन में मौजूद लोगों से गांजे के परिवहन और बिक्री से जुड़े कागजात मांगे गए, लेकिन वे कोई भी दस्तावेज नहीं दिखा पाए। इसके बाद गांजे का वजन किया गया, जो कुल 127.09 किलो निकला। इसकी अनुमानित कीमत करीब 63 लाख 54 हजार 500 रुपये बताई गई है। पुलिस ने गांजे के साथ-साथ घटना में इस्तेमाल कार, दो मोबाइल फोन और 1,500 रुपये नकद भी जब्त किए। इस प्रकार जब्त की गई कुल संपत्ति की कीमत लगभग 72 लाख 71 हजार रुपये आंकी गई है।



बिलासपुर बादाम कांड में नया खुलासा एनओसी के बदले पैसे मांगने का आरोप, विवादित वीडियो हो रहा वायरल



बिलासपुर, 21 अप्रैल 2026। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित बिलासपुर बादाम कांड में एक बार फिर नया मोड़ आ गया है। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की वरिष्ठ सहायक पूनम बंजारे का एक और विवादित वीडियो सामने आने के बाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस वीडियो में एनओसी जारी करने के एवज में पैसे मांगने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। बताया जा रहा है कि एक महिला आवेदक और उसके बेटे को लंबे समय तक ऑफिस के चक्कर लगाए गए। आरोप है कि एक से डेढ़ महीने तक एनओसी जानबूझकर लंबित रखी गई और इस दौरान पैसे की मांग की गई। वायरल वीडियो में महिला आवेदक अधिकारी से गुहार लगाते हुए कहती नजर आ रही है 'मैडम गाली मत दो', जबकि

नवसल मुवत हुआ बस्तर तो अफसरों और ठेकेदारों की हुई मौज घटिया तरीके से बना रहे थे स्कूल भवन, वीडियो हुआ वायरल तो निर्माण पर चला बुलडोजर

बीजापुर, 21 अप्रैल 2026। छत्तीसगढ़ का नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग अब माओवाद से मुक्त हो गया है, सरकारी कामकाज में व्याप्त भ्रष्टाचार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। नक्सलियों के दखल के दौरान कुछ कम होते, जो भी घटिया, वहीं कई निर्माण कार्य तो हुए बिना ही पूरे दर्शा दिए जाते थे। हालात बदलते हैं मगर करणन की जड़ें अब भी गहरी हैं। इसी का जौता जगता नमूना बीजापुर जिले में देखने को मिला, जहां गांव के एक युवक ने घटिया निर्माण कार्य की पोल खोलता हुआ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया। जब यह मामला परवान चढ़ा तब प्रशासन ने पूरे निर्माण कार्य को बुलडोजर चला कर जमींदोज कर दिया। भ्रमरगढ़ ब्लॉक के ग्राम

इतना कमजोर है कि उसे डंडे से आसानी से उखाड़ा जा सकता है। प्रशासन ने चलवाया बुलडोजर : इस घटिया निर्माण को जैसे ही पोल खुली जिला प्रशासन के निर्देश पर इलाके के एसडीएम ने निर्माण कार्य की जांच कराई। इसके बाद बुलडोजर चलाकर पूरे निर्माण कार्य को ध्वस्त कर दिया गया। गौरतलब है कि बस्तर क्षेत्र में नक्सल प्रभाव कम होने के बाद सरकार और प्रशासन शिक्षा के विस्तार पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। दूरस्थ और अंदरूनी इलाकों में स्कूलों का निर्माण कराया जा रहा है, ताकि बच्चों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं मिल सकें। लेकिन इन तरह के घटिया निर्माण कार्य इस प्रयासों पर सवाल खड़े करते हैं।

